THE BUDGET (UTTAR PRADESH), 1996-97.

सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण हमारी संसद को उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। आज जब मैं इस चर्चा में प्रतिभागी हूं, हिस्सा ले रहा हूं तो मैं समझता हूं कि और बहुत सारे माननीय सदस्यों की तरह मेरा मन भी चिंता से ग्रसित है और मेरे मन में भी काफी संसर्न है क्योंकि चार-पांच माह पहले के चुनाव के बावजूद उम्मीदों के बरखिलाफ हर दिन, हर घड़ी, हर प्रयास के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब उत्तर प्रदेश को एक लोकप्रिय सरकार मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयास, बासपा-कांग्रेस के गठबंधन के प्रयास, समाजवादी पार्टी के प्रयास, ये सारे के सारे प्रयास असफल हुए और देश को और मुख्य रूप से हमारे प्रदेश की आम जनता को अभी तक यह सही सूरत में मालूम भी नहीं हो सका है कि हमारी जो लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और संघीय मान्यताएं हैं, उनकी रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश में या राष्ट्र में राजनीति करने वाली पार्टियां इस बात को नहीं समझ सकी हैं कि जनता का जो वर्डिक्ट आया है, उसको सामने रखते हुए वे अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार पा सकें। वैसे तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति यदि आप देखें तो पिछले पांच-छह साल के अंदर चार लोकप्रिय सरकारें मिली हैं लेकिन उन चार लोकप्रिय सरकारों के अगर कामकाज के तरीके को हम देखें तो निश्चित रूप से स्थायित्व न होने के कारण, स्टेबिलिटी न होने के कारण शायद दो साल से ज्यादा कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकी। अठारह महीने, एक साल, डेढ़ साल, दो साल जो भी आप कहें लेकिन दो साल से ज्यादा उसकी अवधि कभी नीहं गई और जब स्थायित्व नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती तो निश्चित रूप से देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था है और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर दबाव पड़ना निश्चित हो जाता है और आज प्रदेश के करोड़ों-करोड़ लोग उसी दबाव के कारण न जाने कितनी परेशानियों के शिकार हो रहे हैं लेकिन इन पिछले छह सालों के अंदर अगर चार बार लोकप्रिय सरकारों का शासन रहा ह तो मैं समझता हूं कि ार बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा है। राष्ट्रपति शासन निश्चित रूप से लोकप्रिय सरकार के मुकाबले कोई अच्छा शासन नहीं होता है। एक संघीय ढांचे के अंदर जनता को यह अधिकार मिलता है कि वह अपने प्रदेश में अपनी पसंद की सरकार बना सके। यह बिलकुल जरूरी नहीं है कि केन्द्र में अगर एक पार्टी की सरकार ह तो प्रदेशों में भी उसी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि पिछले पांच-वह महीनों में जो राजनीतिक वातावरण उभर कर आया है, उससे अंदाजा लगता है कि देश के अंदर केन्द्र में जो सरकार है, येन-केन-प्रकारेण उसके मन में यह बात बैठी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी उसी की पार्टी का शासन होना चाहिए। या जो यूनाइटेड फ्रंट है, उसमें समाहित की हुई पार्टी का होना चाहिए और मैं समझता हूं कि जिद के कारण ऐसी परिस्थिति आयी है जिसकी वजह से लोकप्रिय सरकार अभी भी नहीं मिल सकी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज जब हम इस बजट पर विवेचना कर रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में पानी, बिजली, कृषि, कानून और व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं, राष्ट्रीय औसत आय के कंपैरिज़न में, उसके अनुपात में उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिक की औसत आय, विकास दर योजना, बुनकरों की समस्या और बहुत सारे मामला० हैं, जो एक भयंकर स्थिति बनकर आज उभर आए हैं। यदि नागरिक सुविधाओं के बारे में देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश सरकार एक राजभवन में बंद हो गयी है और निश्चित रूप से मैं गवर्नर के क्रियाकलाप पर तो कोई लांछन नहीं लगाना चाहूंगा, कोई आपत्ति नहीं करना चाहूंगा लेकिन किसी न किसी तरह से आज वह दरवाजे, जो जनता की शिकायतों को सुनने वाले दरवाजे होते हैं, वह बंद हो गये हैं और मुझे यह कहना पड़ेगा कि जनता के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज भी राज्यपाल महोदय के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। वह पत्र जिनके जरिए हम अपने क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं माननीय राज्यपाल को भेजते हैं, उसका पूर्ण रूप से जवाब भी नहीं आ रहा है, उनकी ऐकना लेजमेंट नहीं आ रही है। अगर सरकार ऐसी असंवेदनशील हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका बहुत खराब असर पड़ेगा, चाहे गेहूं के मामले को ले लीजिए, चाहे अनाज के मामले को ले लीजिए, शक्कर के मामले को ले लीजिए, मिट्टी के तेल के मामले को ले लीजिए, आज जिंदा रहने के जो बुनियादी साधन हैं, उनको प्रोवाइड करने की बात को ले लीजिए, मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे अनाज के मंत्री हैं, सिविल सप्लाई के मंत्री श्री यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम यह आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली के मुख्य मंत्री को अपने प्रदेश की जरूरियात को पूरा करने के लिए

जितने गेहूं की जरूरत होगी, हम उसको पूरा करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा, सरकार से जवाब चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग जो इसे समस्या का मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान आपने किया है? आज ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली मे सटा हुआ जिला गाजियाबाद है, उसे देख लीजिए। आज वहां दुकानें खाली पड़ी हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानें आती हैं, वहां अनाज नहीं है। आज जो निर्धारित मिर्ख गेहूं का है, 6 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 40 पैसे है, वह नहीं मिल रहा है और बाजार में गरीब इंसान को 10 रुपये, 11 रुपये और 12 रुपये किलो आटा और गेहूं खरीदकर खाना पड़ रहा है। आज चावल तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मिलता ही नहीं है और शक्कर का भी यही हाल है। हर कार्ड होल्डर को 10 लीटर तेल एक महीने में मिलने का आश्वासन दिया गया है आज उस मिट्टी के तेल की मात्रा घटाकर 5 लीटर-पर कार्ड कर दिया गया है और पांच लीटर तेल भी उसे नहीं मिल पा रहा है, 3 या 4 लीटर मिलता है। लम्बी-लम्बी लाइनों में, कतारों में खड़े होने के बावजूद भी आज हमारे घरों में अंधेरा है। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह इस बात को देखें कि यह कैसे हो रहा है और लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वह उनको क्यों नहीं मिल पा रही है। आज हम योजना के अंदर पिछड़ गये हैं। मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश पीछे चला गया है। आज जो हमारी विकास दर होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय विकास दर निर्धारित की गयी है, वह 6 प्रतिशत है और आज जो ऐवरेज राष्ट्रीय विकास दर, जो दूसरे प्रदेशों के लिहाज से है, वह 4.8 प्रतिशत आती है लेकिन उत्तर प्रदेश में आज 2.4 प्रतिशत विकास दर आकर पहुंची है। हम योजनाओं में विफल हो गये हैं। आज डेफिसिट लाइनेंसिंग के कारण हमारे विकास पर असर पड़ रहा है और अन्य वित्तीय संसाधन, अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की बात तो शायद ऐसे हालात में मुमकिन नहीं हो पाएगी, कोशिश के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है और जब तक अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं जुटाए जाएंगे, इतने बड़े प्रदेश में विकास की आकांक्षा जो हमारे प्रदेश के लोगों ने की है, उसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी?

मान्यवर, 1995-96 के लिए कहा गया था कि 1,700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाये जाएंगे। लेकिन लोकप्रिय सरकार के चले जाने के कारण राष्ट्रपति शासन एक दो साल के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों की किस्मत में आ जाता है। पिछले 1995-96 के वर्ष में केवल 23 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन ही जुटाये जा सके हैं। निश्चित रूप से एक फाइनेन्सियल क्रेंच वहां पर होने जा रहा है। वित्तीय संकट उत्तर प्रदेश के सामने आने वाला है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी लोकप्रिय सरकार की भी है लेकिन राष्ट्रपति शासन के मुकाबले में किसी भी कीमत पर लोकप्रिय सरकार जो है वह ज्यादा बेहतर हुआ करती है। एक न गवर्न करने की सरकार से वह सरकार बेहतर है जो खराब तरीके से गवर्न करे, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में या हमारे प्रदेश में जिस तरह की सरकारें उभर कर आ रही हैं वह तो कोई गवर्न ही नहीं कर रही हैं। आप कानून-व्यवस्था का मसला उत्तर प्रदेश के अन्दर देख लें। आज हर क्षेत्र में एक अजीब तरीके का प्रभाव बढ़ा है। आज अधिकारियों का राजनीतिकरण हो गया है। जो गवर्नर आएगा वह अपने हिसाब से स्थानान्तरण करेगा, जो मुख्य मंत्री आएगा वह अपने हिसाब से स्थानान्तरण करेगा। आज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नौकरशाही के अन्दर इस तरह का व्यवहार हो रहा है और अगर हालत खराब हो जाए, अगर कानून-व्यवस्था चरमरा जाए, अगर वित्तीय संकट हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रशासन में शिथिलता की पराकाष्ठा यह हो गई है कि आज आईएएस एसोसिएशन यह ढूंढती है कि हम में से सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी कौन है, उसको हमें आईडेंटीफाई करना चाहिए। आज हमारी सिविल सर्विसेज कहां जा रही हैं? हमें निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न इस देश के लोकतंत्र और जनतंत्र के सामने आकर खड़ा हो गया है। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने के कारण ही उत्तराखण्ड में एक बहुत ही जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिसको दबाने के लिए काफी प्रयास किए गए, जिसको तोड़ने के काफी प्रयास किए गए लेकिन वह आंदोलन बढ़ता रहा। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों पर असीम कृपा करते हुए लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की कि उत्तराखण्ड को मान्यता दे दी जाएगी और उसे एक नया प्रदेश बना दिया जाएगा, एक नया सूबा बना दिया जाएगा।

मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तरखण्ड बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है बल्कि मुख्य मंत्री ज्योति बसु साहब ने यहां तक कह दिया कि उत्तराखण्ड को राज्य बनाने के वे खिलाफ हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो 13 पार्टियों की सरकार बनी हुई है,

इनकी अपनी एक स्टीयरिंग कमेटी है, इनकी अपनी एक कोआर्डीनेशन कमेटी है, इनके लोग आपस में बैठकर विचार-विमर्श करते हैं और विचार-विमर्श करने के बाद दिल्ली के लाल किले से प्रधान मंत्री जी इस तरह की घोषणा करते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इस बजट के बारे में जवाब देंगे तो बतायेंगे कि उत्तराखण्ड बनने में क्यों देरी हो रही है, उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार विवश हो गई है या सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव पड़ रहा है? इस बारे में आंदोलन एक मर्तबा फिर हो सकता है और अगर लोग ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे तो भयावह स्थिति पैदा हो सकती है और इसका प्रदेश के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। उत्तराखण्ड राज्य अलग से बनाये जाने की घोषणा करने के बाद आज बहुत सारे ऐसे अंचल हैं जहां से एक अलग स्टेट बनाने की बात शुरू हो गई है। ऐसी सूरत में माननीय प्रधान मंत्री जी और उनके सहयोगी मंत्रीगण इस बात को आश्वस्त करायें कि क्या नीति है, क्या दिशा है इस संबंध में, छोटी स्टेट्स बनाये जाने के सिलसिले में वर्तमान सरकार क्या सोचती है।

मान्यवर, आज गरीबी की रेखा के नीचे बसर करने वाले, भारत के संघीय ढांचे में, भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, हमारा देश है, हमारी यूनियन है, हमारा संघ है उसमें उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। एक एसिसमेंट के अनुसार 46.8 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और दूसरे एसिसमेंट के अनुसार 33 प्रतिशत लोग जो हैं वह उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। अब गरीबी की रेखा से उनको ऊपर लाने के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है? मैं याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पहले इस बात की घोषणा की थी और इस बात को कहा था, शिकायत के अंदाज में कहा था और मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत से आने वाले प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश या नार्थ इंडिया की जो सबसे बड़ी पापुलर स्टेट है उसकी दुर्दशा, उसकी कंडीशन, उसकी हालते-जार पर तवज्जो तो की?

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक बीच में और भी हमारे कई माननीय प्रधान मंत्री दिये लेकिन उत्तर प्रदेश पिछड़ा का पिछड़ा रहा। हम यह कहते हैं कि हां उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है लेकिन यह भी गौरव की बात है, यह भी इतिहास में लिखने की बात है कि देश का प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से आता था, देश का दूसरा प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से आता था, देश की तीसरी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से आती थीं, चौथा प्रधान मंत्री राजीव गांधी उत्तर प्रदेश से आता था। बीच में वी पी सिंह साहब आये, चरणसिंह साहब आये, चन्द्रशेखर साहब आये। ये सारे के सारे लोग उत्तर प्रदेश से आते थे लेकिन उसके बावजूद अभी उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश की सार्वभौमिकता, एकता-अखंडता, इतेहाद और देश को जोड़कर रखने के लिए यह जरूरी हो जाता था कि नार्थ का जो प्रधान मंत्री है वह साउथ की तरफ देखे। आज खुशी की बात है कि लगातार पिछले पांच सालों से, पांच साल पहले और अभी भी साउथ से प्रधान मंत्री आया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश से या नार्थ इंडिया से आने वाले प्रधान मंत्री के जमाने में यदि साउथ आगे बढ़ा है तो अब साउथ से आने वाले प्रधान मंत्री के जमाने में उत्तर प्रदेश बढ़ना चाहिये। नार्थ की जो हमारी स्टेट्स हैं वे बढ़नी चाहियें। मैं समझता हूं कि यह केवल घोषणाओं से नहीं होगा। आप जहां जायें वहां दो-चार घोषणाएं कर दें कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया। इसके लिए जरूरत होगी कि आप एक स्पैशल असिसटेंन्ट प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के लिए विशेषतौर पर दें। जो दसवां वित्त आयोग बैठा था उसने कुछ सिफारिशें की थी कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए बहबूद के लिए, उसकी माशी हालत को बेहत्तर से बेहत्तर बनाने के लिए कई हजार करोड़ रुपये स्पेशल अनुदान की सूरत में स्पेशल स्कीम के जरिये दिये जाने चाहियें। जहां तक मुझे याद है करीब 23 हजार करोड़ रुपया दिये जाने की बात कही है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने अब तक कोई ऐसा विशेष अनुदान नहीं दिया है, सिवाय चन्द घोषणाओं के। "हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन/दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।" चलिये, घोषणाएं हुई हैं, उम्मीद है शायद उन पर अमल दरामद भी हो और अमल दरामद होगा तो निश्चित रूप से हमारी तस्वीर, हमारी सूरत पर एक निखार आयेगा।

उत्तर प्रदेश में इस वक्त नीति-निर्धारण नहीं है केवल एड्हॉकिज्म के जरिये उत्तर प्रदेश चल रहा है। खुशी है कि ये बजट आया है लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो फाइनेंसियल क्रन्च का सवाल है, और खासतौर पर इस वक्त जो इसकी फाइनेंसिंग है उसको किस तरह से आप करेंगे, एडिशनल रिसोर्सेस का जो

अपने वायदा किया है उनको किस तरह से जुटा सकेंगे। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

आशा थी, जैसा मैंने शुरू में कहा, राज्य सभा के इलेक्शन के बाद शायद जो हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार है यह अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगी और एक लोकप्रिय सरकार दे सकेगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि यहां इस समय संयुक्त मोर्चा के बहुत महत्वपूर्ण नेतागण बैठे हुए हैं, वे मंत्री भी हैं और उनकी आवाज में असर भी है, अभी पांच-6 महीने पहले भारत के अंदर जो सरकार बनी वह इसी आधार के ऊपर थी कि हमें धर्म-निरपेश शक्तियों को मजबूत बनाना है और हमारे संविधान में संकल्प दिये हुए हैं कि धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि भारतीय नागरिक होने के आधार पर हम इस देश का एक नया कलेवर बनायेंगे, उनको मजबूती देंगे और इसीलिए करीब 140 संसद सदस्य होते हुए भी कांग्रेस ने कहा कि यदि जनता ने यह फैसला किया है कि कांग्रेस को जाना चाहिये तो उसके आगे हम सिर झुकाते हैं। लेकिन धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा सबल बनाने के लिए देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में हम सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आज भी हम उनको समर्थन दे रहे हैं और आगे भी यदि हमारी नीतियों और हमारे कार्यक्रमों के लिहाज से या हमारी आकांक्षाओं के लिहाज से यह सरकार चलती रही तो हम धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए तत्पर हैं लेकिन आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ तो धर्म-निरपेक्षता के आधार पर 140 कांग्रेस के संसद सदस्य आपकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं और एक मॉइनोरिटी गवर्नमेंट जिसके अन्दर तेरह पार्टीज हैं उसके चन्द संसद सदस्य 40 संसद सदस्य, 45 संसद सदस्य होते हुए भी देवेगौड़ा जी को हम प्रधान मंत्री बनाकर देश की नौका खेने की पूरी जिम्मेदारी दिये हुए हैं... तो फिर क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में 65 विधान सभा के सदस्य रखने वाली पार्टी या 33 लोगों की पार्टी, दोनों को मिलाकर—33 को भी छोड़िए, हम कहते हैं कि 65 सदस्यों वाली जो बा०स०पा० पार्टी की मायावती जी हैं, उनके नेतृत्व में, जो बहुसंख्यक समाजवादी पार्टी है या उसके नेतृत्व में चलने वाली अन्य पार्टियां हैं—मैं युनाइटेड फ्रंट को एक एन्टिटी की सूरत में जानकर चल रहा हूं। अब यह कहना कि यू०पी० में आपस में कोई मतभेद हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मौलिक सिद्धांत के आधार पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, बहुसंख्यक समाजवादी पार्टी की कि जिस के 65 विधायक हैं, आपके 150 हों, 140 हों, जितने भी हों, वे सारे के सारे मिलकर वहां एक सरकार बनवा दें और जैसी केन्द्र में सरकार चल रही है और यहां एक छोटी सी पार्टी दूसरी पार्टियों का समर्थन लेकर, एक बड़ी पार्टी का समर्थन लेकर चल रही है वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी पार्टी को बड़ी पार्टी का समर्थन देकर एक सरकार बनाई जा सकती है। यहां कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं है, किसी का एगो हर्ट नहीं होने जा रहा है। सवाल यह है कि बार बार आप सालाना चुनाव कराकर क्या हमारे उस बुनियादी ढांचे को चरमरा देंगे जिसमें कहा गया है कि हर पांच वर्ष के बाद चुनाव हों? अगर हर साल बाद चुनाव होंगे और जिस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना वर्डिक्ट देकर वहां यह स्थिति पैदा की है, अगर इस परिस्थिति में आप कोई विकल्प नहीं निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि यह आप मतदाताओं के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। हमेशा यह कहा गया है कि वह डाली ही झुकती है जिस पर ज्यादा फल आते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वे पार्टियां जो धर्म-निरपेक्षता की दुहाई देती है, लोकतंत्र की दुहाई देती है, एक ऐसे समाज की दुहाई देती है जिस में सर्वहारा वर्ग, पिछड़े लोग, दलित और ऐसे लोग जो हर जाति के उत्थान में विश्वास रखते हैं, वे सब के सब मिलकर एक नया रास्ता खोलें तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बने जो लोकप्रिय सरकार हो और जो धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत पर चले। आज वहां पर लोकप्रिय सरकार न होने की वजह से वहां की जनता बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही है और हर फ्रंट के ऊपर आज उसे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वह अनाज का मामला हो, चाहे वह कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वह नगरपालिकाओं का मामला हो, चाहे सिविल सर्वेन्ट्स का मामला हो, उसे हर फ्रंट पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज वहां पर नगरपालिकाओं का यह हाल हो गया है कि अगर वहां पर रिसोर्स क्रंच का यही हाल रहा तो वहां के कर्मचारियों को वे तनख्वाह नहीं बांट पायेंगे और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भयंकर आग की स्थिति का मुकाबला करने के लिए विवश हो जाएगा।

अनाज के बारे में जैसा मैंने कहा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कौन से ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे युनाइटेड फ्रंट के जो कमिटमेंट्स हैं वे पूरे हो सके। जनवरी, 1997 से वे एक नई प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लायेंगे जिसमें यह देखा जाये कि हमारा वह क्लास, जो घनाड्य क्लास है, जो साधन सम्पन्न

क्लास है वह जो अनाज की सब्सिडी है उसका फायदा वह नहीं उठा सके। अगर वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आप कोई आइडेंटीफिकेशन प्रोग्राम ला रहे हैं जिससे सर्वहारा वर्ग, गरीब लोगों, रिक्शा चालकों, मजदूरों, फोर्थ क्लास इम्पलाईज, दफ्तरों में काम करने वाले बाबू इन लोगों को आपके फेयर प्राइस शाप्स और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का फायदा पहुंचे सके। इसका जो सारा का सारा फायदा होता है वह इन लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए जो इसके लिए डिसर्व नहीं करते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों, काला धंधा करने वाले व्यापारियों के बड़े बड़े अनाज के गोदाम भरे हैं। वही हालत है जैसे एक जमाने में बंगाल में हुआ था। इसलिए अगर यह सरकार नहीं चेती तो शायद बंगाल की कहानी दोहराई जाए जहां पर गोदामों में अनाज भरा हुआ था लेकिन हमारी बहनें और भाई सड़कों पर एड़िया रगड़ रगड़ कर भूख से मर रहे थे। इसलिए निश्चित रूप से ऐक्शन प्रोग्राम इसके लिए बनाना पड़ेगा और जो हार्डर्स हैं उनके यहां डीहोर्डिंग करनी पड़ेगी। जो कालाबाजारी करने वालों के बीच में और एफ०सी०आई० इम्पलाईज के बीच में नैक्सेस बन गया है उसको तोड़ने के लिए बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में आपको कदम उठाने पड़ेंगे। निश्चित रूप से यह केन्द्र का भी सब्जेक्ट है और राज्य का भी सब्जेक्ट है लेकिन इस वक्त यह सब्जेक्ट केवल केन्द्र का है, हम उत्तर प्रदेश पर बात कर रहे हैं क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। केन्द्र की सरकार का वहां ज्यादा से ज्यादा आधिपत्य होते हुए, ज्यादा से ज्यादा उनकी कमान होते हुए यदि प्रदेश की जनता भुखमरी का शिकार हो, एक आतंक की स्थिति वहां है, वहां पर लोग जाते हैं अनाज नहीं मिलता है, लोग बच्चों को भूखा तो नहीं सुला सकते हैं। यदि ऐसी हालत रही तो एक बहुत बड़े आतंक की स्थिति वहां खड़ी हो जाएगी। ऐसी सूरत में कहीं ऐसा न हो कि सरकार उसको कंट्रोल करने में फेल हो जाए। यह हम सब की चिन्ता है, सब राजनीतिक पार्टियों की चिन्ता है और हमारी पार्टी को भी विशेष तौर पर यही चिन्ता है। हमारा मुख्य कर्त्तव्य क्या है? क्या हम जनप्रतिनिधियों का कर्त्तव्य यह है कि किसी न किसी तरह से येन केन प्रकारेण संसद् में पहुंच जाए, विधान सभा में पहुंच जाएं और उसके बाद किसी न किसी तरह से अपनी पार्टी की सरकार बना लें? यदि केवल यही उद्देश्य है तो यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ज़हनियत से अलग ज़हनियत नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इस देश के अन्दर डाऊनफाल केवल इसी कारण हुआ कि उन्होंने उन आंखों से नहीं देखा जो गरीबों के दिल और जज़बात को समझ सकें। आज हम भी कहीं न कहीं इस बुनियादी ज़िम्मेदारी को खो रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारा कर्त्तव्य है और हम सब का यह कर्त्तव्य है कि हम देखें और सरकार को इस बात पर मजबूर करें कि वहां अगर सोती हुई सरकार है तो वह आगे और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अन्दर इस वक्त कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है इसलिए वहां के गवर्नर की सब से ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि जो क्राइसेज़ वहां पर आ रहा है अनाज के सिलसिले में उस क्राइसेज़ से वह किस तरह से निपट सकें।

माननीय, आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की परिस्थिति बड़ी शोचनीय है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने का निर्ख जो 72 से 76 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फिक्स किया था, इसके खिलाफ चीनी मिल मालिक हाई कोर्ट में चले गये और हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया। यह टेक्नीकल ग्राऊंड पर उनके हक में गया और कोर्ट ने यह कहा कि अनाज के मूल्य के मामले में, गन्ने के मूल्य के मामले में, सीरियल्ज के मूल्य के मामले में केन्द्रीय सरकार का ही अधिकार क्षेत्र है और वह ही मूल्य निर्धारित कर सकती है। प्रदेशीय सरकारों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं पहुंचता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि यह तो बहुत दिनों से होता चला आया है, गन्ने की कीमतें हम ही फिक्स करते आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि अगर उनको ऊपर से कोई अप्रूवल लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता रहा है तो वह गलत काम होता रहा है, इसलिए हम इसको अलाऊ नहीं करते। अब केन्द्रीय सरकार को आगे बढ़ना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि आज के जवाब में हमारे मंत्री जी यह कहेंगे कि केन्द्र सरकार 72 और 76 रुपये के हिसाब से फिक्स करती है जो उसने पहले किया था। हालांकि हमारी पार्टी का तो 72 और 76 के हिसाब से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमारा कहना तो यह है कि 82 और 86 रुपये दिया जाना चाहिये। लेकिन इस सिलसिले में केन्द्र सरकार की जो अपनी भूमिका है, जो जिम्मेदारी उसको निभाने के लिए आगे बढ़ना चाहिये। कोर्ट का जो फैसला है वह टेक्नीकल ग्राऊंड पर है उसको दूर करने के लिए मैं समझता हूं केन्द्र सरकार जल्दी चेतेगी।

मान्यवर, जहां तक गन्ने के बकाया का सवाल है, हर साल यह सिचुयेशन आती है, समस्या आती है, इसके लिए भी कोई स्थाई कार्यक्रम केन्द्र सरकार लाएगी और उनका भुगतान कराएगी।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह है कि हमारे सहकारी क्षेत्र में जो चीनी मिलें काम कर रही हैं उनको निजी व्यावसायियों के हाथ, व्यापारियों के हाथ बेचने का षडयंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारा यह तजरुबा रहा है कि पहले भी ऐसा बहुत हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले धंधों को नुक्सान और लाभ के रास्ते पर न चलने की बात कह कर कई प्राइवेट लोगों के हाथ बेचा जा चुका है। ऐसी परिस्थिति के लिए मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देगी।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर आज उर्वरकों की कमी है, पूरे देश के अन्दर कमी है लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और खेती प्रधान प्रदेश है। उस प्रदेश में एक नेक्सस बन गया है बिचौलियों और एजेंट्स का। काफी बढ़ी हुई कीमतों पर उर्वरक किसानों को मिल रहे हैं। पहले तो मिल ही नहीं रहे हैं और अगर मिल रहे हैं तो उनको काफी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसके कारण किसानों का शोषण हो रहा है। और हमें बड़ा गौरव है कि इस वक्त देश का प्रधान मंत्री किसान का एक बेटा है और उनको भी यह बात कहने में गौरव होता है। निश्चित रूप से वे उत्तर प्रदेश के किसानों की जो दुर्दशा है, अपने भाइयों की जो दुर्दशा है, अपने परिवार वालों की जो दुर्दशा है उसकी तरफ तवज्जह देंगे और एक ऐसी स्थिति लाएंगे जिससे यह शोषण रुकेगा। आज जो प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति, मान्यवर मैंने शुरू में कही उसकी तरफ से लोगों का, जनता का ध्यान पूरी तरह से अलग हो गया है इसलिए कि पिछले 6-7 साल के अंदर कहीं संप्रदाय, कहीं जातिवाद, इसी नशे और इसी अफीम में पूरे प्रदेश के लोगों को डाल दिया गया है। इसके कारणवश जो दबाव बनना चाहिए था सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर चाहे वह लोकप्रिय सरकार हो, चाहे वह राष्ट्रपति शासन की सरकार हो वह दबाव नहीं बन सका। मुझे याद आता है कि एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकारें हुकूमत करती थीं तो उत्तर प्रदेश में न जाने कितने आंदोलन होते थे—कभी किसान आंदोलन हो रहा है, कभी मजदूर आंदोलन हो रहा है, कभी सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हो रहा है। अब तो पूरा प्रदेश आंदोलनविहीन हो गया है। आज कहीं भी सड़कों के ऊपर हम और आप, हमारे बहुत सारे लोग, जनता लोग, जनता के नुमाइंदे, जनता को लेकर सड़कों पर आंदोलन के लिए नहीं उतरते हैं क्योंकि उनके साम्प्रदायिकता और जातिवाद का ही इतना नशा हो गया है कि वे अपनी भूख भूल गए हैं, अपनी प्यास भूल गए हैं। लेकिन यह कब तक चलेगा? आज उनको रोजगार की समस्या है, आज उनको भूख और पेट की समस्या है। आज उनकी रोजी-रोटी के मसायल्स हैं, आज उनकी शिक्षा और तालीम के मसायल हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें इस परिस्थिति से उबरना होगा और जनता के लिए जो हमारे सवालात हैं उनके लिए हमें प्रखर होकर आगे आना होगा और यह दंद जो मन के अंदर, जेहन के अंदर, दिमाग के अंदर आ गया है उस दंद से उनको निकालना होगा क्योंकि मुख्य रूप से हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और जन-कल्याण पर यदि प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से यह किसी जाति या धर्म का नुक्सान नहीं होता है यह जो मौलिक हम और आप हैं, जो इन्सान हैं, जो नागरिक हैं और खास तौर से जो हमारे समजोर नागरिक हैं हमारे पिछड़े हुए सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, हमारे वे लोग जो ज्यादा बढ़कर अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनका है। उनके लिए हमारी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एक ऐसा पब्लिक रजिस्टेंस बनाएं, एक ऐसे आंदोलन का मोर्चा शुरू करें जो उनके हितों की रक्षा कर सके।

मैं, मान्यवर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इतना समय दिया। निश्चित रूप से इस बजट का तो हम समर्थन करते ही हैं लेकिन समर्थन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि एक रूटीन की सूरत में यह बजट आए। हमें आशा है आप नये दीप जलाएंगे जहां अंधेरा है वहां रोशनी फैलाएंगे और वे समस्याएं जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उन समस्याओं से उत्तर प्रदेश को उबार सकेंगे। मुझे ऐसी आशा है कि आप जब एक नये संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश के जो हमारे करोड़ों करोड़ लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। धन्यवाद।

ہونا چاہیئے - مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتا ہے کہ پچھلے پانچ چھ مہینوں میں جو اجینٹک واتاورن ابھر کر آیا ہے - اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دیش کے اندر کیندر میں جو سرکار ہے - یعنی - کیبی - پرکار میں اسکے من میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اتر پردیش کے اندر بھی اسی کی پارٹی کا شاسن ہونا چاہیئے - یا جو یونائیٹڈ فرنٹ ہے - اسمیں سمجھتی کی ہوئی پارٹی کا ہونا چاہیئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ضد کے کارن ایسی پرستھتی آئی ہے جسکی وجہ سے لوک پریئے سرکار ابھی بھی نہیں مل سکی - مانیہ ور - میں آپکے مادھیم سے اپنی بات اسپشٹ کرنا چاہونگا کہ آج جب ہم اس بجٹ پر وچار وِمرش کر رہے ہیں - وچار وِمرش کر رہے ہیں تو اتر پردیش میں پانی - بجلی - کرشی - قانون اور ویوستھا - ناگرک سویدھائیں راشٹریہ اوسط آئے کے کمپیرژن میں اسکے انوپات میں اتر پردیش میں رہنے والے ناگرک کی اوسط آمدنی - وِکاس وِرودھی

بنکروں کی سمسیا اور بہت سارے معاملات ہیں - جو ایک بھینکر اسستھتی بنکر آج ابھر آئے ہیں - یدی ناگرک سویدھاؤں کے بارے میں دیکھا جائے تو آج اتر پردیش کے کارن شاید دو سال سے زیادہ کوئی بھی سرکار اتر پردیش میں نہیں چل سکی - اٹھارہ مہینے - ایک سال - ڈیڑھ سال - دو سال جو بھی آپ کہیں دو سال سے زیادہ اس کی اودھی کبھی نہیں گئی اور جب اسستھائتو وِرودھ نہیں ہوتا - اسمبلیشی نہیں ہوتی تو نشچت روپ سے دیش کی جو آرتھک ویوستھا ہے - پردیش کی سماجک ویوستھا ہے اور پردیش کی پرشاسنک ویوستھا ہے - اس پر دباؤ پڑنا نشچت ہو جاتا ہے اور آج پردیش کے کروڑوں - کروڑ لوگ اس دباؤ کے کارن نہ جانے کتنی پریشانیوں کے شکار ہو رہے ہیں - لیکن ان پچھلے چھ سالوں کے اندر اگر چار بار لوک پریئے سرکاروں کا شاسن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چار بار اتر پردیش میں راشٹرپتی شاسن بھی رہا ہے - راشٹرپتی شاسن نشچت روپ سے لوک پریئے سرکار کے مقابلے میں کوئی اچھا شاسن نہیں ہوتا ہے - ایک سمجھوتے کے ڈھانچے کے اندر جتنا کوئی یہ ادھیکار ملتا ہے کہ وہ اپنے پردیش میں اپنی پسند کی سرکار بنا سکیں - یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ کیندر میں اگر ایک پارٹی کی سرکار ہے تو پردیشوں میں بھی اس پارٹی کی سرکار

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم اشوست کرتے ہیں کہ دلی کے ملکھیہ منتری کو اپنے پردیش کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے جتنے گیہوں کی ضرورت ہوگی - ہم اسکو پورا کرینگے - میں پوچھنا چاہونگا - سرکار سے جواب چاہونگا کہ آج اتر پردیش کی ذمہ داری آپکے اوپر ہے آپ بتائیے کہ اتر پردیش کے کروڑوں لوگ جو اس سمسیا کا مقابلہ کر رہے ہیں - انکے لئے کیا پراودھان آپنے کیا ہے آج زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے - دلی سے سٹا ہوا ضلع غازیاباد ہے - اسے دیکھ لیجئے آج وہاں دکانیں خالی پڑی ہیں - جو ساد و وترن پرنالی کے تحت دکانیں آتی ہیں - وہاں اناج نہیں ہے - آج جو نردھارت نرخ گیہوں کا ہے - چھ روپئے پچاس پیسے ہے - وہ نہیں مل رہا ہے - اور بازار میں غریب انسان کو ۱۰ روپئے گیارہ روپئے اور بارہ روپئے کلو آٹا اور گیہوں خرید کر کھانا پڑ رہا ہے - آج چاول تو سادھارن وترن پرنالی کی دوکانوں پر ملتا ہی نہیں ہے اور شکر کا بھی یہی حال ہے - ہر کارڈ ہولڈر کو دس لیٹر تیل ایک مہینے میں ملنے کا آشوا سن دیا گیا ہے - آج اس مٹی کے سرکار ایک دانہ بھوکوں میں بند ہو گئی ہے اور مشیت روپ سے میں کہوں تو کرفیو کرپا کلاپ پر تو کوئی لاچھن نہیں لگانا چاہونگا کوئی آپتی نہیں کرنا چاہونگا لیکن کسی نہ کسی مرحلے سے آج وہ دروازے - جو جنتا کی شکایتوں کو سننے والے دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں - اور مجھے یہ کہنا پڑیگا کہ جنتا کے چنے ہوئے نمائندوں کی آواز بھی راجیہ پال مہودے کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے - وہ پتر جنکے ذریعے ہم اپنے چھیتر کے لوگوں کی سمسیائیں ما ننیہ مہودے راجیہ پال کو بھیجتے ہیں اسکا پورن روپ سے جواب بھی نہیں آ رہا ہے - انکی ایکسنا لیجمنٹ نہیں آ رہی ہے اگر سرکار ایسی ایسنوپیوں شیل ہو جائیگی تو نشچیت روپ سے اسکا بہت خراب اثر پڑیگا - چاہے گیہوں کے معاملے کو لے لیجئے چاہے اناج کے معاملے کو لے لیجئے - شکر کے معاملے کو لے لیجئے مٹی کے تیل کے معاملے کو لے لیجئے - آج زندہ رہنے کے جو بنیادی سادھن ہیں - انکو پروائیڈ کرنے کی بات کو لے لیجئے - میں کہنا چاہونگا کہ ابھی جو ہمارے اناج کے منتری ہیں - سہکاری صیلاری کے منتری شری یادو جی

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

لگانے کی بات تھی مشاید ایسے حالات میں ممکن نہیں ہو پائیگی - کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو پا رہا ہے - اور جب تک ترک تعلق و تیئے سنسادھن نہیں جٹا پائیں گے - اتنے بڑے پردیش میں وکاس کی آکانشا جو ہمارے پردیش کے لوگوں نے کی ہے - اسکی پورتی کیسے ہو پائیگی - مانیہ ور - 96-1995 کیلئے کہا گیا تھا کہ ۱۷۰۰ کروڑ روپئے کے ترک و تیئے سنسادھن جٹائے جائینگے لیکن لوک پریئے سرکار کے چلے جانے کے کارن اور راشٹرپتی شاسن لگ جانے کے کارن برابر کچھ نہ کچھ ایک دو سال کے بعد اتر پردیش کے لوگوں کی قسمت میں آ جاتا ہے - پچھلے 96-1995 کے ورش میں کیول ۳۰۰ کروڑ روپئے کے ترک و تیئے سنسادھن ہی جٹائے جا سکے ہیں - نشچت روپ سے یہ ایک فائنانشیل کرینچ وہاں پر ہونے جا رہا ہے - وتیئے سنکٹ اتر پردیش کے سامنے آنے والا ہے - اسکی بہت ساری ذمہ داری لوک پریئے سرکار کی بھی ہے - لیکن راشٹرپتی شاسن کے مقابلے میں کسی بھی قیمت پر لوک پریئے سرکار جو ہے - وہ زیادہ بہتر ڈھنگ سے کر سکتی ہے - ایک خرابی کے ساتھ گورن کرنے کی سرکار تیل کی ماترا گھٹا کر پانچ لیٹر پر کارڈ کر دیا گیا ہے اور پانچ لیٹر تیل بھی اسے نہیں مل پا رہا ہے - تین یا چار لیٹر ملتا ہے - کبھی کبھی لائنوں میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے - یہ لیجنڈ سرکار کی ذمہ داری ہے - راجیہ پال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے - اور لوگوں کی جو بنیادی سوبدھائیں ہیں - وہ انکو کیوں نہیں مل پا رہی ہیں آج ہم یوجنا کے اندر پچھڑ گئے ہیں - مانیہ ور - اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھویں پنچ ورشیئے یوجنا میں اتر پردیش پیچھے چلا گیا ہے - آج جو ہماری وکاس در ہونی چاہیئے جو راشٹریہ وکاس در نردھارت کی گئی ہے وہ وچھ پرتیشت ہے اور اسوچ راشٹریہ وکاس در جو دوسرے پردیشوں کے لحاظ سے ہے - وہ چار اعشاریہ آٹھ پرتیشت ہے - لیکن اتر پردیش میں آج دو اعشاریہ چار پرتیشت وکاس در ہو کر رہ گئی ہے - ہم یوجناؤں میں پچھڑ گئے ہیں - آج ڈفیٹ فائیننسنگ کے کارن ہمارے وکاس پر اثر ہو رہا ہے - اور دوسرے وتیئے سنسادھن - اترپت وتیئے سنسادھن

[ ] Transliteration in Arabic Script.

پرشن اس دیش کے لوک تنتر اور جن تنتر کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا ہے۔ چھیتر پکے استھان بڑھ رہا ہے۔ اور چھیتر پکے استھان بڑھنے کے کارن اترا کھنڈ میں ایک بہت ہی زبردست آندولن ہوا۔ جسکو دبانے کیلئے گولی پر یاس کئے گئے ہیں۔ جسکو تو ڑنے کے گولی پر یاس کئے گئے ہیں۔ لیکن وہ آندولن بڑھتا گیا مجھے خوشی ہے کہ مانیئے پردھان منتری جی نے اتر پردیش کے لوگوں پر اسیم کرپا کرتے ہوئے لال قلعے کے پراچیر سے اس بات کی گھوشنا کی اترا کھنڈ کو مانیتا دے دی جائیگی۔ اور اسے ایک نیا پردیش بنا دیا جائیگا۔ ایک نیا صوبہ بنا دیا جائیگا۔

مانیہ ور آپ جانتے ہیں کہ اترا کھنڈ بنانے کیلئے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ بلکہ ملکھیہ منتری جیوتی بسو صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اترا کھنڈ کو راجیہ بنانے کے وہ خلاف ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو تیرہ پارٹیوں کی سرکار بنی ہوئی ہے انکی اپنی ایک اسٹیرنگ کمیٹی ہے انکی اپنی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے۔ انکے لوگ اسمیں بیٹھکر وچار وِمرش کرتے ہیں۔ اور وچار وِمرش کرنے کے بعد دلی کے لال قلعے سے پردھان منتری جی اسطرح کی گھوشنا کرتے ہیں

سے وہ سر کا بہتر ہے۔ جو خراب طریقے سے کوڑن کرے۔ لیکن آج جو اتر پردیش میں یا ہمارے پردیش میں جسطرح کی سرکاریں ابھر کر آرہی ہیں وہ تو کوی گٹھ بندن ہی نہیں کر رہی ہیں۔ آپ قانون و یوستھا کا معاملہ اٹھا کر اتر پردیش کے اندر دیکھ لیں آج ہر چھیتر میں ایک عجیب طریقے کا بھاؤ بڑھ رہا ہے۔ آج ادھیکاریوں کا راجنیتیکرن ہو گیا ہے۔ جو گورنر آئیگا وہ اپنے حساب سے تبادلے کریگا۔ جو مکھیہ منتری آئیگا وہ اپنے حساب سے تبادلے کریگا۔ آج جاتی کے آدھار پر۔ دھرم کے آدھار پر نوکرشاہی کے اندر اسطرح کا ویوہار ہو رہا ہے۔ اگر حالات خراب ہو جائے اگر قانون و یوستھا چرمرا جائے۔ اگر وِتیہ ویوستھا خراب ہو جائے۔ اور پرشاسن میں نیچے جانے کی ہماری پرا کاشٹھا یہ ہو گئی ہے۔ کہ آج آئی۔ اے۔ ایس۔ ایسوسی ایشن یہ ڈھونڈتی ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بھرشٹ ادھیکاری کون ہے۔ اور اسکو ہمیں آئیڈیل بنیفیائی کرنا چاہیئے۔ اور آج ہماری سمعل سرو سیز کہاں جا رہی ہے۔ ہمیں نشچت روپ سے اس پر دھیان دینا ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں ایک اسسمنٹ کے مطابق ۲۸ پرسینٹ لوگ غریبی کی ریکھا کے نیچے رہتے ہیں اور دوسرے اسسمنٹ کے مطابق ۳۳ پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ اتر پردیش میں غریبی کی ریکھا کے نیچے رہتے ہیں اب غریبی کی ریکھا سے اتنوا اوپر لانے کیلئے وہ وہ تمام سرکار کوشش کر رہی ہے۔ میں یاد دلانا چاہونگا کہ مانیئے پردھان منتری جی نے کچھ دن پہلے اس بات کی گھوشنا کی تھی اور اس بات کو کہا تھا اور شکایت کے انداز میں کہا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ دکشن بھارت سے آنے والے پردھان منتری نے اتر پردیش یا ناردھ انڈیا کی جو سب سے بڑی پاپولر اسیشٹ ہے اسکی درد شا اسکی کنڈیشن۔ اسکی حالت زار پر توجہ تو کی۔

مانیئے پردھان منتری جی نے کہا کہ اس اتر پردیش نے جواہر لال نہرو سے لیکر راجیو گاندھی تک بیچ میں اور بھی ہمارے پانچ چھ سات مانیئے پردھان منتری دیئے لیکن اتر پردیش پچھڑا کا پچھڑا رہا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اتر پچھڑا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی گورو کی بات ہے یہ بھی اتہاس لکھنے کی بات ہے کہ دیش کا تو میں سمجھتا ہوں کہ مانیئے منتری جی اب اس بجٹ کے بارے میں جواب دینگے تو آپ بتایئے کہ اتر اکھنڈ بننے میں کیوں دیری ہو رہی ہے۔ اسکے کیا کارن ہیں اور کیا سرکار دوش ہو گئی ہے۔ یا سرکار کے اوپر کسی طرح کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس بارے میں آنند ون ایک مرتبہ پھر ہو سکتا ہے۔ اور لوگ ایسا راستہ اختیار کرینگے۔ تو خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اسکا پردیش کے وکاس پر برا اثر پڑیگا۔ اتر اکھنڈ راجیہ الگ سے بنائے جانے کی گھوشنا کرنے کے بعد سے آج اتر پردیش کے اندر کے بہت سارے انچل ہیں جہاں سے ایک الگ اسیٹ بنانے کی بات شروع ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں مانیئے پردھان منتری جی اور انکی سمبھوگی منتری گن اس بات کو آشوست کریں کہ کیا نیتی ہے کیا دشا ہے اس سمبندھ میں۔ چھوٹی اسیٹس بنائے جانے کے سلسلہ میں اس کی موجودہ۔

مانیئے ور۔ آج غریبی کی ریکھا کے نیچے بسر کرنے والے۔ بھارت کے منگھے ڈھانچے میں۔ بھارت کا جو سنگھ روپ ہے ڈھانچہ ہے۔ ہمارا دیش ہے۔ ہماری یونین ہے۔ ہمارا سنگھ ہے اسمیں اتر پردیش کے اندر

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

سے نہیں ہوگا - آپ جہاں جائیں وہاں دو چار گھوشنائیں کر دیں - یہ ہمنے آپکو دیا - ہمنے آپکو وہ دیا - اسکے لئے ضرورت ہوگی کہ آپ ایک اسپیشل اسسٹینس پروگرام اتر پردیش کیلئے خاص طور پر دیں جو دسواں وتیئے آیوگ بیٹھا تھا اس نے کچھ سفارشیں کی تھیں کہ اتر پردیش کا فرق کیلئے - پسماندہ کیلئے اسکی معاشی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے کئی ہزار کروڑ روپیہ اسپیشل انوداں کی صورت میں اسپیشل اسکیم کے ذریعے دیئے جانے چاہئے - جہاں تک مجھے یاد ہے قریب ۳۰ ہزار کروڑ روپیہ دیئے جانے کی بات کہی ہے - لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش میں آپنے کو نساو شیش انودان دیا ہے - سوائے چند گھوشناؤں کے ہمکو معلوم ہے - جنتا کی حقیقت - لیکن دل کو بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے - چلئے گھوشنائیں ہی سہی - امید ہے شاید ان پر عمل درآمد بھی ہو اور عمل درآمد ہوگا تو نشچت روپ سے ہماری تصویر - ہماری صورت پر ایک نکھار آ جائیگا -

اتر پردیش میں اسوقت نیتی نردھارن نہیں ہے - کیول ایڈھاکم کے ذریعے اتر پردیش چل رہا ہے - خوشی ہے کہ یہ بجٹ آیا ہے لیکن پردھان منتری جواہر لال نہرو اتر پردیش سے آتا تھا - دیش کا دوسرا پردھان منتری لال بہادر شاستری اتر پردیش سے آتا تھا - دیش کا تیسرا پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی اتر پردیش سے آتی تھیں چوتھا پردھان منتری راجیو گاندھی اتر پردیش سے آتا تھا - یہ میں وی - پی سنگھ صاحب آئے - چندر شیکھر صاحب آئے یہ سارے کے سارے لوگ اتر پردیش سے آئے تھے لیکن اسکے باوجود ابھی اتر پردیش پچھڑا ہوا ہے - جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تو دیش کی سارہ ہو سکتا - ایکتا اکھنڈتا اتحاد اور دیش کو جوڑ کر رکھنے کیلئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ نارتھ کا پردھان منتری ہے - وہ ساؤتھ کی طرف دیکھے - آج خوشی کی بات ہے کہ لگاتار پانچ سالوں سے ابھی پانچ سال پہلے اور ابھی ساؤتھ سے پردھان منتری آیا ہے - اب یہ آپکی ذمہ داری ہے کہ اتر پردیش سے یا نارتھ انڈیا سے آنے والے پردھان منتری کے زمانے میں اگر ساؤتھ آگے بڑھا ہے تو ساؤتھ سے ہونے والے پردھان منتری کے زمانے میں اتر پردیش بڑھنا چاہیئے - نارتھ کی جو ہماری اسپیشس ہیں وہ بڑھنی چاہیئے - میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیول گھوشنائیں

[†] Transliteration in Arabic Script.

نے کہا کہ اگر جنتا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس کو جانا چاہیے تو اسکے لئے ہم سر جھکاتے ہیں لیکن دھرم نرپیکشتا شکتیوں کو زیادہ سے زیادہ سیل بنانے کیلئے دیوگوڑا جی کے تیتر تو میں ہم سرکار کو سمرتھن دینے کیلئے تیار ہیں ہم آج بھی ہم انکو سمرتھن دے رہے ہیں۔ اور آگے بھی اگر ہماری نیتیوں اور ہمارے کاریہ کرموں کے لحاظ سے یا ہماری آکانشاؤں کے لحاظ سے یہ سرکار چلتی رہی تو ہم دھرم نرپیکشتا کے مضبوط سدھانت کو اور زیادہ مضبوط بنانے کیلئے بھی سدھ ہیں ہیں۔ لیکن آپکی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک طرف تو دھرم نرپیکشتا کے آدھار پر ۱۴۰ کانگریس کے سنسد سدسیے آپکی سرکار کو سمرتھن دے رہے ہیں۔ اور ایک مائناریٹی گورنمنٹ جس میں تیرہ (۱۳) پارٹیاں ہیں اسکے چند سنسد سدسیے ۱۰ سنسد سدسیے ۵۰ سنسد سدسیے ہوتے ہوئے بھی دیوگوڑا جی کو ہم پردھان منتری بنا کر دیش کی نوکا کھینے کی پوری ذمہ داری دیئے ہوئے ہیں۔ ... تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اتر پردیش میں ۵۶ پردھان سبھا سدسیے رکھنے والی پارٹی کیا ۳۳

ہم دیکھتے ہیں کہ اسکا جو فائنانشیل کرپنچ کا سوال ہے جیسا میں نے کہا اور خاص طور پر اس وقت جو اسکی فائنانسنگ ہے اسکے لئے آپ کریں گے۔ ایڈیشنل رسورسیز کا جو آپنے وعدہ کیا ہے انکو کس طرح سے جٹا سکیں گے۔

آج امیدھی جیسا میں نے شروع میں کہا۔ راجیہ سبھا الیکشن کے بعد شاید جو ہماری سنیکت مورچہ سرکار ہے یہ اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیگی اور ایک نوک پر پیئے سرکار دے سکے گی۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کیونکہ یہاں اسوقت سنیکت مورچے کے بہت اہم لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ منتری بھی ہیں اور انکی آواز میں اثر بھی ہے۔ ابھی پانچ چھ مہینے پہلے بھارت کے اندر جو سرکار بنی وہ اسی آدھار کے اوپر تھی کہ ہمیں دھرم نرپیکشتا شکتیوں کو مضبوط بنانا ہے اور ہمارے سنودھان میں سنشودھن دیئے ہوئے ہیں کہ دھرم اور جاتی کے آدھار پر نہیں بلکہ ناگرک ہونے کے آدھار پر ہم اس دیش کا ایک نیا آکار بنائینگے۔ انکو مضبوطی دی جا سکتی ہے اور اسی لئے قریب ۱۰ سال سنسودھن کے ہوتے ہوئے بھی کانگریس

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

کا ایجنڈ ہرٹ ہونے نہیں جا رہا ہے سوال یہ
ہے کہ بار بار آپ سال نا چناؤ کرا کر کیا بھاری
اس بنیادی ڈھانچے کو جو مرا دینے جسمیں
کہا گیا ہے کہ ہر پانچ ورش کے بعد چناؤ ہوں۔
اگر ہر سال بعد چناؤ ہونگے اور جسکے جس
پر ستھتی میں اتر پردیش کے لوگوں نے اپنا
ووٹ لیکر دیکر وہاں یہ استھتی پیدا کی ہے
اگر اس پر ستھتی میں آپ کوئی وکلپ
نہیں نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
آپ مت داتاؤں کے ساتھ انیائے نہیں
کریں گے۔ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے۔ کہ وہ ڈالی
ہی جھکتی ہے جس پر زیادہ پھل لگتے ہیں۔
آج اتر پردیش کے اندر وہ پارٹیاں جو
دھرم نرپیکشتا کی دہائی دیتی ہیں۔ لوک
تنتر کی دہائی دیتی ہیں۔ ایک ایسے سماج

کی دہائی دیتی ہیں۔ جسمیں سروہارا
ورگ۔ پچھڑے ورگ۔ دلت اور ایسے ورگ
جن جاتی اتھان میں وشواس رکھتے ہیں
وہ سب کے سب ملکر ایک نیا راستہ
کھولیں تو انکی ذمہ داری بنتی ہے۔ کہ وہ
ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے اتر
پردیش کے اندر ایک ایسی سرکار بنے
جو لوک پریہ سرکار ہو اور دھرم نرپیکشتا
کے سدھانت پر چلے۔ آج وہاں پر لوک پریہ

لوگوں کی پارٹی۔ دھرموں کو ملا کر ۳۰ سو کو
بھی چھوڑیئے ہم کہتے ہیں کہ ۶۵ سدسیوں
والی جو بی۔ ایس۔ پی۔ پارٹی کی جو
مایاوتی جی ہیں۔ انکے نیتر تو میں۔ جو
بہو سنکھیک سماجوادی پارٹی ہے یا
اسکے نیتر تو میں چلنے والی دوسری پارٹیاں
ہیں۔ میں یونائیٹیڈ فرنٹ کو ایک اینٹیٹی
کی صورت میں جانکر چل رہا ہوں۔ اب یہ
کہنا کہ یو۔ پی۔ میں آپس میں کوئی
مت بھید ہیں۔ اس پر میں نہیں جانا
چاہتا۔ لیکن مولک سدھانت کے
آدھار پر آپکی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔
بہو سنکھیک سماجوادی پارٹی کی جسکے
۶۵ ودھایک ہیں۔ آپکے ایک سو پچاس
ہوں۔ ایک سو چالیس ہوں۔ جتنے بھی
ہوں۔ وہ سارے کے سارے ملکر وہاں ایک
سرکار بنوا دیں۔ اور جیسی لیکنڈ میں
سرکار چل رہی ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹی
سی پارٹی دوسری پارٹیوں کا سمرتھن
لیکر۔ ایک بڑی پارٹی کا سمرتھن لیکر چل
رہی ہے۔ ویسے ہی اتر پردیش میں ایک
چھوٹی سی پارٹی کو بڑی پارٹی کا سمرتھن
دیکر ایک نئی سرکار بنائی جا سکتی ہے۔
یہاں کوئی پرسٹیج کا سوال نہیں ہے۔ کسی

†| | Transliteration in Arabic Script.

وہ اسکا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسکے لئے کیا ہے کوئی آئیڈینٹیفکیشن پروگرام لانا ہے ہیں جس سے سرو ھار اور گ - غریب لوگوں رکشا چالکوں - مزدوروں - فورتھ کلاس امپلائز دفتروں میں کام کرنے والے بابو ان لوگوں کو آپنے فیئر پرائس شاپس اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کا فائدہ پہونچ سکے - اسکا جو سارا کا سارا فائدہ ہوتا ہے . وہ ان لوگوں کو نہیں مل پاتا - اسلئے جو اسکے لئے ڈیزرو نہیں کرتے ہیں - انکو اسکا فائدہ نہیں ملنا چاہیے - آج اتر پردیش میں وپاپاریوں - کالا دھندا کرنے والے وپاپاریوں کے بڑے بڑے گودام اناج کے بھرے پڑے ہیں - وہی حالت ہے - جیسے ایک زمانے میں بنگال میں ہوا تھا - اسلئے اگر یہ سرکار نہیں ہوشیار ہوتی تو شاید بنگال کی کہانی دھرائی جائے

جہاں پر گوداموں میں اناج بھرا ہوا تھا لیکن ہماری بہنیں - ہمارے بھائی سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوک سے مر رہے تھے - اس لئے نقشہ روپ سے ایکشن پروگرام اسکے لئے بنانا پڑیگا - اور جو ہارڈ رس ہیں - انکے یہاں کمی ہو تو سرنگ کرنی پڑیگی - جو کالا بازاری کرنے والے کے بیچ میں اور ایف - سی - آئی - امپلائز کے بیچ میں نیکسس

سرکار نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی جنتا بہت بڑی قیمت ادا کر رہی ہے - اور ہر فرنٹ کے اوپر آج ہمیں ایسی تمام دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے - چاہے وہ اناج کا معاملہ ہو - چاہے وہ خانون ویوستھا کا معاملہ ہو - چاہے وہ نگر پالیکاؤں کا معاملہ ہو - چاہے وہ سول سرونٹس کا معاملہ ہو - اسے ہر فرنٹ پر دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے - آج وہاں پر نگر پالیکاؤں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہاں پر اسسٹنس کریننچ کا یہی حال رہا تو وہاں کے کرمچاریوں کو وقت تنخواہ نہیں بانٹ پائینگے - اور اتر پردیش ایک بہت بڑی بھینٹ آگ کی اسستھی کا مقابلہ کرنے کیلئے سودش ہو جائیگا -

اناج کے بارے میں جیسے میں نے کہا - میں مانتا ہوں منتری جی سے جاننا چاہونگا کہ وہ کونسے ایسے قدم اٹھا رہے ہیں - جس سے یونائیٹڈ فرنٹ کے جو کمٹمنٹس ہیں وہ پورے ہو سکیں - جنوری ۱۹۹۷ سے وہ ایک نئی پرنالی لا رہے ہیں - سادہ جنک وتر پرنالی لا رہے ہیں - جسمیں یہ دیکھا جائے کہ ہمارا وہ کلاس - جو امیر کلاس ہے - جو سادھن سمپن کلاس ہے - وہ جو اناج کی سبسڈی ہے - اسکا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکے - اگر

میں پہنچ جائیں۔ وہ وہاں سبھا میں پہنچ جائیں۔ اور اسکے بعد کسی نہ کسی طرح سے اپنی پارٹی کی سرکار بنالیں۔ اگر کیول یہی مقصد ہے تو وہ برٹش سامراجیہ وادی ذہنیت سے الگ ذہنیت نہیں ہے برٹش سامراجیہ واد کا اس دیش کے اندر خاتمہ ہوگیا ہے کیول اسی کارن ہوا کہ انھوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا جو غریبوں کے دل اور جذبات کو سمجھ سکیں۔ آج ہم بھی کہیں نہ کہیں اس بنیادی ذمہ داری کو کھو رہے ہیں۔ چھوڑ رہے ہیں۔ اسلئے نشچت روپ سے ہمارا فرض ہے اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں اور سرکار کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہاں اگر صوتی بھوئی سرکار ہے تو وہ جائے اور خاص طور پر اتر پردیش کے اندر اسوقت تو کسی بھی پریکار سرکار نہیں ہے اسلئے وہاں سے گورنر کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ کہ جو کرائسیز وہاں پر آرہا ہے۔ اناج کے سلسلے میں اس کرائسیز سے وہ کس طرح سے نبٹ سکیں۔

مانیہ ور۔ آج اتر پردیش میں کتنا کسان کی پرستھتی بڑی شوچنیئے ہے۔ اتر پردیش کی سرکار نے گنے کا جو نرخ ۱۷۵ روپئے ۱۷ روپئے فی کوئنٹل کے حساب سے طئے کیا تھا اسکے بدلے گیا ہے اسکو تو اسنے کیلئے بڑی بیری کے ساتھ اتر پردیش میں آپکو قدم اٹھانے پڑیں گے نشچت روپ سے اگر کیندر کا بھی سبجیکٹ اور راجیہ کا بھی سبجیکٹ ہے۔ لیکن اسوقت یہ سبجیکٹ کیول کیندر کا ہے۔ ہم اتر پردیش پر بات کر رہے ہیں۔ کیوں کہ وہاں پر اشٹر وپتی شاسن لگا ہوا ہے۔ کیندر کی سرکار وہاں زیادہ سے زیادہ ادھی پتیہ ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اتنی کمان ہوتے ہوئے اگر پردیش کی جنتا بھکمری کا شکار ہو۔ ایک آتنک کی استتھی وہاں ہے وہاں پر لوگ جائے ہیں اناج نہیں ملتا ہے۔ لوگ بچوں کو بھوکا تو نہیں سلا سکتے ہیں۔ اگر ایسی حالت رہی تو ایک بہت بڑے آتنک کی استتھی وہاں کھڑی ہو جائیگی۔ ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار اسلحہ کنٹرول کرنے میں خیال ہو جائے۔ یہ ہم سبکی چنتا ہے۔ سب راج نیتک پارٹیوں کی چنتا ہے۔ اور ہماری پارٹی کی وشیش طور پر یہی چنتا ہے۔ ہمارا مکھیہ کرتویہ کیا ہے۔ کیا ہم جن پر تینڈھیوں کا کرتویہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پیس کیں سرکاریں سنسد

†Transliteration in Arabic Script

روپئے دئے جانے چاہئے۔ لیکن اس سلسلہ میں لیگنڈو سرکار کی جو اپنی بھومکا ہے۔ جو ذمہ داری ہے اسکو نبھانے کیلئے آگے بڑھنا چاہئے۔ کورٹ کا جو فیصلہ ہے۔ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہے اسکو دور کرنے کیلئے میں سمجھتا ہوں لیگنڈو سرکار جلدی چیتے گی۔

مانیہ ور جہاں تک گنے کی بقایا کا سوال ہے۔ ہر سال یہ سیچوایشن آتی ہے سمسیا آتی ہے۔ اسکے لئے بھی کوئی استھائی کارپئے کی لیگنڈو سرکار لائے گی۔ اور انکا بھگتان کرائے گی۔

مانیہ ور۔ آج اتر پردیش میں ایک بہت بڑا پرشن ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارے سہکاری چھیتر میں جو چینی ملیں کام کر رہی ہیں۔ انکو کچھ ویوسائیوں کے ہاتھ دیا پاریوں کے ہاتھ بیچنے کی سازش چل رہی ہے۔ اتر پردیش میں ہمارا تجربہ رہا ہے۔ کہ پہلے بھی ایسا بہت ہو چکا ہے۔ سارو جنک چھیتر میں کام کرنے والے دھندوں کو نقصان اور لابھ کے رستے پر نہ چلنے کی بات کہکر کئی پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ بیچا جا چکا ہے۔ ایسی پرستھتی کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ لیگنڈو سرکار پورن روپ سے دھیان دیگی۔

خلاف چینی مل مالک بھائی کورٹ میں چلے گئے۔ اور بھائیو کورٹ نے انکے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر انکے حق میں کیا اور کورٹ نے یہ کہا کہ اناج کے مولیہ کے معاملے میں۔ گنے کی قیمت کے معاملے میں۔ سیریلز کی قیمت کے معاملے میں لیگنڈو سرکار کا ہی ادھیکار چھیتر ہے اور وہ ہی قیمتیں طے کر سکتی ہے۔ صوبائی حکومتوں کو اسطرح کا کوئی ادھیکار نہیں پہونچتا ہے۔ اتر پردیش کی سرکار نے کورٹ میں یہ بھی کہا کہ یہ تو بہت دنوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ گنے کی قیمتیں ہم ہی فکس کرتے آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگر انھوں اوپر سے کوئی ایرو ول لینی پڑتی ہے۔ یا نہیں لینی پڑتی ہے۔ لیکن کورٹ نے انکی اس دلیل کو نہیں مانا۔ کورٹ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو وہ غلط کام ہوتا رہا ہے۔ اسلئے ہم اسکو الاؤ نہیں کرتے۔ اب لیگنڈو سرکار کو آگے بڑھنا چاہئے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے جواب میں ہمارے منتری جی یہ کہینگے کہ لیگنڈو سرکار ۷۲ اور ۷۶ روپئے کے حساب سے فکس کرتی ہے۔ جو اسنے پہلے کیا تھا۔ حالانکہ ہماری پارٹی کا تو ۷۲ اور ۷۶ کے حساب سے بھی سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ ۸۲ اور ۸۶

†Transliteration in Arabic Script

مانیہور - ہمارے اتر پردیش کے اندر آج اور لوگوں کی کمی ہے - پورے دیش کے اندر کمی ہے لیکن اتر پردیش ایک بڑا پردیش ہے - اور کھیتی پردھان پردیش ہے - اس پردیش میں ایک مینیجمنٹ بن گیا ہے - بجلیوں اور ایجینیٹکس کا - کافی بڑھی ہوئی قیمتوں پر اور ورت کسانوں کو مل رہے ہیں - پہلے تو مل ہی نہیں رہے ہیں - اور اگر مل رہے ہیں تو انکو کافی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے - اسکے کارن کسانوں کا شوشن ہو رہا ہے - اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ اسوقت دیش کا پردھان منتری کسان کا ایک بیٹا ہے - اور انکو بھی یہ بات کہنے میں فخر ہوتا ہے - نشچت روپ سے وہ اتر پردیش کے کسانوں کی جو درد شا ہے - اپنے بھائیوں کی جو درد شا ہے اپنے پریوار والوں کی جو درد شا ہے اسکی طرف توجہ دینگے - اور ایک ایسی استھتی لا ئینگے - جس سے یہ شوشن رکیگا - آج جو پردیش کی استھتی آرتھک استھتی - مانیہور میں نے شروع میں بھی اسکی طرف سے لوگوں کا جنتا کا دھیان پوری طرح سے الگ ہو گیا ہے اسلئے کہ پچھلے چھ سات سال کے اندر کہیں سمپردائے - کہیں جاتیواد اسی نشے اور اسی افیم میں پورے پردیش کے لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے - اسکے کارن دیش جو دباؤ بننا چاہئے تھا - سرکار کے اوپر شاسن کے اوپر چاہے وہ روک پر پہنچے سرکار ہو - چاہے وہ راشٹرپتی کی سرکار ہو - وہ دباؤ نہیں بن سکا - مجھے یاد آتا ہے - کہ ایک زمانہ تھا جب کانگریس کی سرکاریں حکومت کرتی تھیں - تو اتر پردیش میں نہ جانے کتنے آندولن ہوتے تھے - کبھی کسان آندولن ہو رہا ہے - کبھی مزدور آندولن ہو رہا ہے - کبھی سرو ہارا ورگ کے حقوق کی رکشا کیلئے ہو رہا ہے - اب تو پورا پردیش آندولن

وہیں ہو گیا ہے - آج کہیں بھی سڑکوں کے اوپر ہم اور آپ - ہمارے بہت سارے لوگ - جنتا کے لوگ - جنتا کے نمائندے - جنتا کو لیکر سڑکوں پر آندولن کیلئے نہیں اترتے ہیں - کیونکہ انکو سامپردائیکتا اور جاتیواد کا ہی اتنا نشا ہو گیا ہے - کہ وہ اپنی بھوک بھول گئے ہیں - اپنی پیاس بھول گئے ہیں - لیکن یہ کب تک چلیگا - آج انکو روزگار کی سمسیا ہے - آج انکو بھوک اور پیٹ کی سمسیا ہے - آج انکی روزی روٹی کے مسائل ہیں - آج انکی شکشا اور تعلیم کے مسائل ہیں - اسلئے نشچت روپ سے ہمیں اس پر استھتی سے

†Transliteration in Arabic Script

میں یہ بجٹ آئے - ہمیں امید ہے کہ آپ
نئے دیپ جلائیں گے - جہاں اندھیرا ہے وہاں
روشنی پھیلائیں گے - اور وہ سمسیائیں
جو دن پر دن کی سمسیائیں ہیں ان
سمسیاؤں سے اتر پردیش کو آباد کریں گے
مجھے ایسی آشا ہے کہ آپ جب ایک نئے
سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پردیش
کے جو بھاوی کروڑوں لوگ ہیں انکی
سمسیاؤں کا سمادھان ہو سکے گا -
دھنیہ واد - "ختم شد"

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारे सिब्ते रज़ी साहब ने बहुत माकूल बातें कीं। उनका भी शुक्रिया। जिस रास्ते से वे अंदर आते हैं इस सदन में उस रास्ते के बाहर लिखा हुआ है—"सत्यं वद, धर्म्म चर"। पता नहीं उन्होंने पढ़ा की नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो सच बातें भी कुछ कहते और सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान दुर्दशा के लिए पूरी तौर पर वे परिस्थितियां उत्तरदायी हैं जो उन नेताओं ने पैदा की हैं जिनकी वकालत सिब्ते रज़ी साहब ने की है और स्वयं उनकी पार्टी भी उसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। सच्चायी यही है। यही हकीकत है।

यह बजट जो पेश किया गया है, लगभग चार हजार करोड़ के घाटे का बजट, उसे अगर पढ़ लिया गया होता तो पता चलता कि इस बजट में है क्या। यह बजट एक ऐसी सरकार का बजट है जिसका आज जनता से कुछ भी लेना देना नहीं। यह बजट एक ऐसी सरकार का बजट है जो मुसलसल असत्य पर आधारित है।

बात किसानों की करते हैं। बजट में देखिए कृषि के लिए जो खर्चा होना चाहिए था उसे घटा दिया गया। बड़ी अजीब बात है। एक सरकार जो किसानों की बात करे और जब किसानों की बेहतरी की बात आए तो कहे कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं? वह कहां पर बढ़ाये? राजभवन के खर्च पर बढ़ा दे। हजूर, राजभवन पर खर्चा बढ़, जाये, जेलों पर होने वाला खर्चा बढ़ जाए, पुलिस

اجرنا ہوگا اور جتنا کیلئے ہمارے سوالات
ہیں اتنے ہمیں پر کھر ہو کر آگے آنا ہوگا -
اور یہ دوند جو دل کے اندر - دھرم کے
اندر دماغ کے اندر آگیا ہے - اس دوند سے
اپنو نکالنا ہوگا کیونکہ مکھیہ روپ سے
ہمارا دیش ایک کلیانکاری راجیہ
ہے - اور کلیان پر اگر پربھاؤ پڑتا ہے -
تو نشچیت روپ سے یہ کسی جاتی یا دھرم
کا نقصان نہیں ہوتا ہے - جو مولک ہم ہیں
اور آپ ہیں جو انسان ہیں - جو ناگرک
ہیں اور خاص طور سے جو ہمارے کمزور
ناگرک ہیں - ہمارے پچھڑے ہوئے سمودھا
ورگ کے لوگ ہیں - ہمارے وہ لوگ جو
زیادہ پڑھکر اپنی بات نہیں کہہ سکتے ہیں
انکا ہے - اتنے سے ہماری یہ ذمہ داری ہو
جاتی ہے - کہ ہم ایک ایسا پبلک ریزیشن
بنائیں - ایک ایسے آندولن کا مورچہ
شروع کریں جو دبے کچلوں کی رکشا کر
سکے -

میں مانیہ ور - آپکو بہت بہت دھنیہ واد
دینا چاہوں گا کہ آپنے مجھے اتنا وقت دیا -
نشچیت روپ سے اس بجٹ کا تو ہم سمرتھن
کرتے ہی ہیں - لیکن سمرتھن کا مطلب یہ
نہیں ہونا چاہیے - کہ ایک دوشپورن صورت

†Transliteration in Arabic Script

पर होने वाला खर्च बढ़ जाए, लेकिन पशुपालन पर खर्च नहीं बढ़े और कृषिकर्म पर खर्चा नहीं बढ़े? हमने वर्ष 1995-96 में कृषिकर्म पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे जो इस बार हम 17 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। 20 करोड़ से 17 करोड़ कर दिया। हमने तीन करोड़ घटा दिया। यह कैसे किसानों की बात हो गई? इसका कौन जिम्मेदार है? अगर यह सरकार सच बोलती होती कि यह किसानों की रहनुमाई करती है तो कम से कम उत्तर प्रदेश के बजट में किसानों पर जो खर्चा किया जा रहा है उसे घटाती तो नहीं। लेकिन उसे घटाया। अब आप देखिए कि सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है और सड़कों पर क्या खर्चा किया जा रहा है। सड़क और सेतु पर मात्र 16 करोड़ रुपया हम सालों से खर्च करते चले आ रहे हैं और वही दोहरा दिया गया। यह कैसा बजट हुआ? हमारे सिब्ते रज़ी साहब ने सड़कों पर चलते हुए देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कें नहीं हैं। हजूर, उत्तर प्रदेश में अब सड़कों के स्थान पर गड्ढे हैं। अब गड्ढे को सड़क मान लीजिए तो बात अलग है। बड़ी अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वहां पर हर मामले में हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। यह ठीक है कि कुछ शिक्षा पर खर्चा बढ़ाया है लेकिन पूंजी पर पूरे साल में कितना खर्च किया? हम केवल 6 करोड़ रुपया नए स्कूल वगैरह बनवाने पर खर्चा करना चाहते हैं, जबकि पुलिस पर हम भारी रकमें बढ़ा देना चाहते हैं। जेलों पर हम भारी रकमें बढ़ा देना चाहते हैं। पुलिस पर हम 1,169 करोड़ रुपये के स्थान पर 1,371 करोड़ रुपये और कारागार पर 63 करोड़ के स्थान पर 93 करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। पुलिस पर इन्होंने थोड़ा सा खर्चा ज्यादा बढ़ाया है। केवल दो सौ करोड़ रुपया बढ़ाया है। अब दो सौ करोड़ रुपया जब पुलिस पर बढ़ा दिया गया, अगर इसको गांवों की ओर देख लिया जाता, स्कूलों की ओर देख लिया जाता, और अस्पतालों की ओर देख लिया जाता तो कितना अच्छा रहता? यह कैसी सरकार है और यह कैसी जनता की रहनुमाई कर रही है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I find no Cabinet Minister here. I hope the Minister for Parliamentary Affairs is noting down the points.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am noting down the points.

श्री नरेन्द्र मोहन: यह देखिए, "सत्यम वथ, धर्मम चर"। यह तो सत्यवादी हैं और हम पर बड़े लांछन लगा रहे हैं। संक्षेप में तो सिब्ते रजी साहब ने भी कह दिया कि धर्म निरपेक्ष शक्तियां, पंथ निरपेक्ष शक्तियां ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बजट के ऊपर बोलिए।

श्री नरेन्द्र मोहन: हां, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बजट की ही बात कर रहा हूं।.....**(व्यवधान)** उपसभाध्यक्ष जी, मैं केवल बजट की बात कर रहा था, लेकिन.....। मैंने मंत्री जी को जगाने के लिए कुछ बातें कह दीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह जगे हुए हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवर सवाल यह है कि जो सरकार किसानों की बात करे, गरीबों की बात करे और जब वह राजभवन पर अधिक धन खर्च करना चाहती है तो संकेत क्या मिलता है? संकेत क्या मिलता है जब यह सरकार स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं करना चाहती?

मान्यवर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बहुत दौरे किए। वह बहुत अच्छी बात थी और बड़ी घोषणाएं की। अब उन सारी घोषणाओं को ले लिया जाए तो उस पर लगभग तीन हजार करोड़ का खर्चा आएगा। अब अगर इस तीन हजार करोड़ रुपयों का भारत सरकार अनुदान ही उत्तर प्रदेश को दे दे तो कम-से-कम वह घोषणाएं तो पूरी हो जाएं जोकि प्रधान मंत्री जी ने की है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस बजट में उन घोषणाओं का कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, ऐसा लगता है कि धोखा-धड़ी के सहारे चुनाव जीतने के लिए भारी बातें की गयी। यह ढपोरशंखी प्रवृत्ति क्यों? मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर कब तक इस देश की जनता के साथ, विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इस तरह का असत्य बोला जाएगा? उन घोषणाओं का क्या अर्थ है जो आप ने की और जिन के लिए आप ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया? क्या आप की उन घोषनाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मान्यवर, वह घोषणाएं क्या हैं? अगर देखना चाहें तो उन की पूरी एक लिस्ट है और उस में लगभग 12-14 घोषणाएं हैं जिन में सर्वाधिक घोषणाएं यह की गयीं की उत्तर प्रदेश में तमाम नए-नए बिजली के उत्पादन केन्द्र स्थापित कर दिए जाएंगे। एक जगदीशपुर में होगा और जिलों में भी होगा। आनपारा के

लिए पैसा नहीं है, उस के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था दिखायी नहीं दे रही। यह क्या बात हुई? फिर एक घोषणा प्रधान मंत्री जी ने की कि सड़कें बनवा दी जाएंगी, नए पुल बनवा दिए जाएंगे। लेकिन पैसा कहां है, काहे से बनवाएंगे पुल? मान्यवर, कम-से-कम जब प्रधान मंत्री कोई घोषणा करे तो केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह उस ओर ध्यान दे। मुझे तो यह लगता है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने जो बजट बनाकर भेजा, उसे भारत सरकर ने देखा नहीं और उसे जैसे-का तैसा यहां भेज दिया गया क्योंकि अगर देखा होता तो इतनी बड़ी गलती वह न करती। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने किस बिना पर घोषणाएं की? मैं तो आप के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि वह घोषणाएं जो उन्होंने की थीं, क्या अब उन के लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया जाएगा या नहीं? उपसभाध्यक्ष जी मैं आप के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर वह प्रावधान नहीं करते है तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता से क्षमा मांगेंगे और अगर वह क्षमा नहीं मांगते है तो क्या यह भारत के संविधान के साथ धोखा-धड़ी नहीं है? भारत की जनता के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ धोखा-धड़ी नहीं है? यह कौनसी बात हुई कि प्रधान मंत्री जाते हैं और घोषणाएं कर के चले आते हैं, लेकिन केन्द्र उन के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं करता है?

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश मे ऊर्जा के लिए, इनर्जी के लिए मात्र एक रुपए का प्रावधान किया गया है? वहां नई योजनाओं के नाम पर हम केवल इस वर्ष एक रुपया खर्च करेंगे? यह क्या स्थिति बनी? यह उत्तर प्रदेश का कौनसा माखौल उड़ाया जा रहा है? उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से भारत सरकर को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए आज कोई नई योजनाएं नहीं है। सन् 2004 तक उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई नई योजना आने वाली नहीं है। कोई नया बिजली का उत्पादन केन्द्र बनने वाला नहीं है। जो प्रावधान किए गए है, वे आधे-अधूरे हैं और अगर उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं मिलेगी तो उस का विकास कहां से होगा?

सिब्ते रज़ी साहब ने सही कहा कि सारे मुल्क की लगभग साढ़े छः प्रतिशत की ग्रोथ है और उत्तर प्रदेश की 2.4 प्रतिशत, यह क्या बात हुई? आखिर देश में सर्वाधिक गुरबत, गरीबी, निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी, भुखमरी उत्तर प्रदेश में ही क्यों? क्या इसलिए कि हमारे राज्य से बहुत प्रधान मंत्री आए—6 या 7 प्रधान मंत्री आए, नेहरू जी आए? इसलिए हमें गरीबी में रहना होगा? हमें नहीं चाहिए प्रधान मंत्री, हमें तो उत्तर प्रदेश की खुशहाली चाहिए ये कांग्रेस सरकारें थीं जो इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में राज करती रहीं, केन्द्र में राज करती रहीं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने केवल गरीबी दी, भुखमरी दी, अशिक्षा दी यह कैसे हो गया? **(व्यवधान)**

श्री गया सिंह: यदि प्रधान मंत्री नहीं चाहिए तो वाजपेयी जी का क्या होगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी यू०पी० के बजट पर चर्चा हो रही है।

श्री नरेन्द्र मोहन: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बजट पर ही चर्चा कर रहा हूं अब सवाल यह उठता है कि लोक निर्माण पर हम इस बार मात्र 18 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, जबकि पहले हम अधिक खर्च करते थे यह 18 करोड़ जो खर्च किया जा रहा है, यह सारे का सारा नॉन-प्लान में है, प्लान में नहीं है यह स्थिति क्या है? क्या हम उत्तर प्रदेश में कोई नया निर्माण कार्य नहीं करना चाहेंगे? अब केवल तीन महीने बचे हैं, मार्च में यह साल पूरा हो जाएगा इन तीन महीनों में और कुछ नहीं हो सकता था तो कम से कम यह बतया जा सकता था, यह बता दिया जाता है कि हम अगले साल क्या करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए। इस बारे में भी कोई संकेत नहीं किया गया, बताया गया कि राज्य विधान मंडल में जो चुनाव कराए गए, इन सारे चुनावों पर सवा दो सौ करोड़ रुपए खर्च हुए और इस वर्ष भी, 1996-97 में, 154 करोड़ रुपए और चाहते हैं। क्या चुनाव आने वाले हैं? आप क्या संकेत दे रहे हैं? चुनाव पर जो खर्च हुआ है सवा दो सौ करोड़ रुपया, पिछले चुनावों पर और इस वर्ष भी 154 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे तो यह संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो बात साफ तौर से कह दी जानी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, सवा दो सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद चुनाव हुए, विधान सभा चुनकर आई लेकिन उसके सदस्यों को अभी तक शपथ नहीं दिलाई गई। अब यह 154 करोड़ रुपए खर्च होकर जब अगले चुनाव होंगे और उसके बाद जो सदस्य चुनकर आएंगे तो क्या उनको भी शपथ नहीं दिलाई जाएगी? यह हो क्या रहा है? **(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: शपथ क्या बजट के कारण रुकी हुई है जो प्रावधान करा दिया जाए?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): इनको बोलने दीजिए, अभी आपका भी मौका आ रहा है।

श्री नरेन्द्र मोहन: मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उचित यह होगा कि अगर चुनाव कराएं जाएं तो चुनावों के बाद जो स्थिति बने, उसको स्वीकार करके कम के कम विधायकों को शपथ तो दिलवा दी जाए। यह तय उत्तर प्रदेश की विधान सभा करे कि उसे अगला चुनाव कराना है या नहीं कराना है, यह तय केन्द्र सरकार क्यों करना चाहती है? यह तय राज भवन में क्यों हो? यह राज भवन में तय न हो कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा क्या चाहती है, यह विधान सभा में तय हो।

उत्तराखंड की बात की गई प्रधान मंत्री ने उत्तराखंड के लिए आश्वासन दिया, ठीक कहा सिब्ते रज़ी साहब ने, मैं उन्हें बधाई देता हूं उत्तराखंड के विकास के नाम पर तो इन्होंने जरूर रुपया रखा है, मैं पढ़ता हूं, इसमें लिखा है:—

"राज्य के उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मिलने की संभावना है"

लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की जाएगी? उत्तराखंड राज्य बने, इसके लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा? इसके लिए भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए। उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के लिए जो 225 करोड़ रुपए रखे गए हैं, वह अपनी जगह ठीक है लेकिन उत्तराखंड की जनता अब इस प्रकार के प्रावधानों से संतुष्ट होने वाली नहीं है।

महोदय, अंत में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की भलाई करनी है तो राजनीतिक पक्षपात से रहित होकर, पर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हमें कुछ सोचना होगा तभी बात बनेगी। यह बजट तो मेरी दृष्टि में धोखाधड़ी है। इसमें इतनी राशि भी नहीं रखी गई है जितना कि केन्द्र सरकार ने हमको अनुदान देने की बात कही है। यह कितना कम है। आप देखिए कि केन्द्र सरकार से अग्रिम के रूप में हमको इस वर्ष मात्र 3,451 करोड़ रुपया मिलेगा जब कि विभिन्न आकलनों के हिसाब से उत्तर प्रदेश को हर वर्ष लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपया मिले, तभी इस राज्य का विकास हो सकता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अब वह उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान देना प्रारंभ करें तो उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश की समस्याओं का कुछ निदान हो सके। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश के बजट पर बोलने का अवसर दिया। वैसे तो यह बजट लखनऊ की विधानसभा में पेश होना चाहिए था और यह स्थिति सुखद नहीं है कि इसको आज संसद में पेश करना पड़ रहा है। लेकिन विवशता है और विवशता इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी एक पक्ष या किसी एक दल के पक्ष में अपना बहुमत व्यक्त नहीं किया है। यह स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती है क्योंकि जनता के द्वारा चुनी जाने वाली राज्य सरकार का विकल्प यह संसद केवल विवशता में ही हो सकती है। इसलिए यह काम हमें आज यहां करना पड़ रहा है। वहां की व्यवस्था चलाने के लिए हमें वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करना पड़ रहा है अन्यथा व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। इसी विवशता के तहत यह बजट यहां लाया गया है। महोदय, मैं इस संसद में उपस्थित सभी पक्षों से अपने हृदय के अंतर से एक प्रश्न करना चाहता हूं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, हमारा जनता दल भी और कांग्रेस पार्टी भी है। मैं सबके विचारार्थ एक प्रश्न बहुत विनम्रता से यहां रखना चाहता हूं। आज हम सबके लिए यह स्थिति दुःखद है और चिंतनीय है कि लोकप्रिय सरकार वहां क्यों नहीं बन पाई? किसी एक दल के पक्ष में स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं आया? भाजपा के लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि हमें सरकार नहीं बनाने दी गई। अभी माननीय नरेन्द्र मोहन जी ने भी यह बात कही है और बहुत से सदस्य भी कह रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, यह आपके लिए भी चिंतनीय बात है क्योंकि चुनाव में तो आप गए थे। आज तक आप कोई सूची प्रस्तुत कर नहीं पाए कि किसके सहारे आप बनाना चाहते हैं।....**(व्यवधान)**

श्री लक्खीराम अग्रवाल: यह आपने हृदय की बात नहीं कही।....**(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह उलझन और यह कंफ्यूजन इतना है भाजपा में कि उनके पास एक प्रतिनिधि नहीं है बात कहने के लिए, कई को उठना पड़ता है। यह तो कठिनाई है।...**(व्यवधान)**

श्री लक्खीराम अग्रवाल: जो उधर बैठे हुए है उनके मन में कंफ्यूजन है इसके कारण सरकार नहीं बन पाई।

श्री सोमपाल: अगर आप मुझे बात पूरी कर लेने देते तो शायद यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेश्वर सिंह: जो आप कह रहे हैं वह क्या मन से कह रहे हैं?

श्री सोमपाल: हां, मन से। चूंकि आप आए नहीं थे इससे पहले मैंने कहा था कि मैं मन से कह रहा हूं। इसलिए आपने सुना नहीं था। अज्ञान वश आप यह बात कह रहे हैं।

मेरे लिए भी विचारणीय है, समाजवादी पार्टी के लिए भी विचारणीय है, कांग्रेस के लिए भी विचारणीय है, जितने भी दल इससे सम्बद्ध हैं सब के लिए विचारणीय और चिंतनीय बात है और यह आत्म-निरीक्षण का एक अवसर हमें मिला है। यह कहा जाता है कि जनादेश स्पष्ट नहीं है। जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। जनादेश ने यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं देना चाहती। क्योंकि उनका अनुभव एक पार्टी के शासन का बहुत अच्छा नहीं रहा जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश और इस देश की दुर्गति हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं। जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। जनादेश ...**(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र मोहन: वहां सरकार अपने दल की बना लें।

श्री सोमपाल: हमारे दल की सरकार जहां बननी चाहिए थी वहां बनी हुई है।...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बजट पर तो पहुंचे ही नहीं हैं, अब आप आगे आ जाइए।

श्री नरेन्द्र मोहन: हम लोग इनको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में अवश्य बनालें।

श्री सोमपाल: देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मॉडल जनता दल ने सरकार बनाकर यहां केन्द्र में पेश किया है वह आज जनता को स्वीकार्य है। वह एक दल के बहुमत को पसंद नहीं करते, एक दल के बहुमत के आचरण से वह आश्वस्त नहीं रहे। इसी कारण उन्होंने ...**(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र मोहन: इसीलिए सिब्ते रज़ी साहब ने आलोचना की है।...**(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा कठिन हो जाएगा। जब माननीय नरेन्द्र मोहन जी बोल रहे थे तो एक छोटी सी चुटकी मैंने अवश्य ली थी, पर व्यवधान नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, अब जब महिला बोलती है तो थोड़ा बहुत तो आकर्षण हो ही जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह जो उत्तर प्रदेश का जनादेश आया है और जो केन्द्र के संबंध में जनादेश आया है हम जितने भी जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी दल हैं उन सबको इससे एक संदेश, एक सबक सीखना चाहिए कि अब आगे यह एक दल की सरकार के बहुमत वाला रिवाज समाप्त होने जा रहा है। सदा इसी प्रकार हुआ करेगा, क्योंकि लोग अपना मतदान करने के बाद स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं क्योंकि एक दल को बहुमत दे दिया और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं है और उनकी जो आशाएं एक दल से थी वह पूरी नहीं हो पाई। यह तो वह अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार या दूसरी प्रकार की इस तरह की चीजें जो जनता के हित की नहीं है उसमें वह सरकारें पड़ जाती है। तो मतदाता यह चाहता है कि सरकार इस प्रकार की बने जिसके अंदर उसकी सुरक्षा के लिए इस तरह की अंतर-निहित व्यवस्थाएं रहे। वह तभी हो सकती है जब इस तरह की कई दलों की सरकारें बने। उत्तर प्रदेश में भी यही होना चाहिए कि अगर वहां लोकप्रिय सरकार बनानी हो तो आपसे...**(व्यवधान)** इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकीन नाथ चतुर्वेदी): बोल लेने दीजिए।

श्री सोमपाल: मैं यह कहना चाहता था कि यह विचारणीय बात है कि सब दलों को मिलकर यह बात सोचनी चाहिए कि जनता की जो दुर्गति है...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब दूसरी विचारणीय बातों पर आ जाएं।

श्री सोमपाल: मैं आ रहा हूं। जो जनता की दुर्गति हमने की है वह किन कारणों से, इसलिए उन्होंने स्पष्ट जनादेश दिया कि वह किसी भी एक दल को और मेरी मान्यता यह है, मेरी अपनी भावना यह है.....**(व्यवधान)**

श्रीमती मालती शर्मा: यह बजट पर नहीं बोल रहे हैं।.....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): सोमपाल जी, मेरी तरफ देखकर ही बोले जिससे कोई आकर्षण न हो.....**(व्यवधान)**

कई दलों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी यह सोचना पड़ेगा कि आपको बार-बार जनादेश में क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, क्यों नकारा जा रहा है। कहीं कुछ न कुछ खामी और कुछ न कुछ कमी रह गई.....**(व्यवधान)**

श्री नेरन्द्र मोहन: भाजपा को रिजेक्ट नहीं किया गया।

श्री महेश्वर सिंह: न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी।

श्री सोमपाल: चलिए आप ले आइए कोई ऐसी राधा जो नाच ले। हम तो आप वाली को देख लेंगे कि आपके पास कोई ऐसी राधा है।.....**(व्यवधान)**.....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बजट पर आ जाइए.....**(व्यवधान)**.....

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बजट की बात जहां आती है तो बजट आखिरकार है क्या? बजट में आम आदमी जो उस प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था की मूल इकाई है, वह अपने श्रम से जो कुछ कमाई करता है, जो कुछ धन संग्रह करता है, उसका एक भाग सरकार करों के मायम से लेकर यह वचन देती है कि हम इसको आपके विश्वास के चलते हुए अपने पास रखेंगे और जन-कल्याण के कार्यों के लिए इसका व्यय करेंगे पर अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखें तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में तो सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश ऊपर से चौथी स्थिति में था और आज नीचे से चौथी स्थिति में है। मुझे याद है 1 नवम्बर, 1966 को जब हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था पंजाब राज्य से अलग होकर, उस समय हरियाणा के प्रति-व्यक्ति की आय से उत्तर प्रदेश के प्रति-व्यक्ति की आय दोगुना थी और आज हरियाणा के प्रति-व्यक्ति की आय से उत्तर प्रदेश के प्रति-व्यक्ति की आय तीन गुना है, यह स्थिति है। यह ठीक कहा माननीय सिब्ते रज़ी ने, अब चले गए हैं, कि सात प्रधाना मंत्री तो पहले और एक प्रधान मंत्री बारह-तेरह दिन के लिए माननीय वाजपेयी जी सारे उत्तर प्रदेश के रहे और उसके बाद राज्य की यह स्थिति? अगर इस वर्तमान भयावह स्थिति का ब्यौरा देना मैं शुरू करूं तो यह सर्वदिश है, सर्वतोमुखी है कि कोई विभाग, समाज का कोई अंग, सरकार का कोई अंग ऐसा नहीं बचा जिसकी दुर्दशा न हुई हो पर मैं केवल कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अधिकारियों और जनसाधारण में जितना अनिश्चितता का वातावरण और जितना अनिश्चितता का भाव वर्तमान समय में है, उतना उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। हर छह महीने में अधिकारियों के स्थानान्तरण किए जाते हैं। मैं जिस स्थायी समिति का अध्यक्ष हूं गृह कार्य संबंधी, उसके समक्ष भी यह बात आई थी कि उत्तर प्रदेश के ज़िलाधिकारी स्तर के अधिकारियों का कार्यकाल औसतन चार से छह महीने है और सारा ध्यान सरकार का इसी पर रहता है कि ज़िलाधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वे सारा दिन राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि उनके पिट्ठू और उनके दलाल पर्चियां दे देते हैं पैसे लेकर और उनको अच्छी-अच्छी जगहों पर लगा दिया जाता है। मेरी मान्यता तो यह है कि इस बजट में भी जितना प्रावधान किया गया है, यदि उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं, वे स्वयं जाकर देखें तो शायद ही कहीं जन-कल्याण के किसी कार्य के निर्माण की उपस्थिति का भान आपको होता होगा। न कहीं सड़क बन रही है, न विद्यालय बन रहा है, न कोई नया निर्माण कार्य हो रहा है। केवल सांसदों के जो स्थानीय क्षेत्र विकास की योजना केन्द्रीय सरकार ने लागू की है, उनके साईन-बोर्डों के अलावा कहीं कोई सार्वजनिक निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है।

हमारी सड़कें आप देख लीजिए चाहे वह गांवों को एक-दूसरे से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग हों, उत्तर प्रदेश के राजमार्ग हों, केन्द्र के राजमार्ग हों या दूसरी सड़कें हों, जितनी दुर्गति सड़कों की उत्तर प्रदेश में है संभवतः उत्तर भारत में तो इतनी दुर्गति सड़कों की कहीं नहीं है। हमारे बहुत प्रसिद्ध और आदरणीय नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया राजमार्ग जो शाहदरा से सहारनपुर तक जाता है, 160-170 किलोमीटर लंबा है। एक दिन हम वहां गए थे तो मुझे हंसी में कहना पड़ा जब किसी ने कहा कि यह कितनी दुर्गति है और कितना हमारा अपमान है कि माननीय चरण सिंह जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और इसके ऊपर न कार चल सकती है, न मोटर चल सकती है, न ट्रक चल सता है। तो मैंने यह कहा कि इसका नाम ठीक चरण सिंह मार्ग रखा गया है कि चरणों के द्वारा इस पर चला जा रहा है। कार इसके ऊपर चल ही नहीं सकती, इसका नाम कार मार्ग नहीं है, चरण सिंह मार्ग है और यह

बिलकुल उपयुक्त नाम है और उसी के अनुरूप इसकी स्थिति बनी हुई है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति आप देखिए। मैं उत्तर प्रदेश के केवल तीन-चार पश्चिमी ज़िलों की बात कहता हूं। मैं मेरठ से आता हूं और पिछले तीन वर्ष में 68 हत्याएं प्रति माह का औसत है मेरठ ज़िले में और मुजफ्फरनगर जिले में 75 का है। मुजफ्फरनगर जनपद को उत्तर प्रदेश ही नहीं, संभवतः भारत का सबसे अमीर जिला प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से माना जाता है लेकिन अगर अपराध की संख्या देखें तो भी वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर है, शीर्षस्थ है। उत्तर प्रदेश माफिया गिरोह की रणस्थली बना हुआ है और पुलिस के सामने सबका नाम है, उनके नाम बताए भी जाते हैं किन्तु उसके बाद भी उन्हें खुली छूट है। उसमें एक राजनीतिक दल नहीं, सारे राजनीतिक दल सम्मिलित हैं और वह उन माफियाओं को खुला संरक्षण देते हैं। खाली संरक्षण नहीं देते बल्कि उन्हें अपने दलों में भी उच्च पदों पर रखते हैं और वह लम्बी-लम्बी कई कई किलो की पीतल की प्लेट लगाकर चलते हैं कि यह हमारे दल का सचिव है। यह फलां जिले का जिला अध्यक्ष है और वही लोग सारे अपराध की वृत्ति में लगे हुए हैं। यही स्थिति वहां न्यायालयों की है। न्यायालयों की क्रिया के विषय में जिसे ज्यूडिशियल ऐक्टीविज़म कहा जाता है, जैसे न्यायालय तो सारा कुछ ठीक कर देंगे? उत्तर प्रदेश में अगर आप जाकर देखें तो मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, इन जिलों में तो अपराध जितने बढ़े हैं, उसमें न्यायालयों की सबसे बड़ी भूमिका है। पुलिस के ऊपर एक तरह से रूकावट डालने का काम न्यायालय कर रहे हैं। वहां वकीलों का सिवाय इसके कोई काम नहीं है कि माफिया गिरोह और अपराधियों की वकालत करें और जिला न्यायधीश भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यह चीज़ किसी भी समय सत्यापित की जा सकती है, वैरीफाई की जा सकती है। बसों की लूट जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उतनी शायद ही पूरे हिन्दुस्तान में हो। आए दिन बस लूट ली जाती है। गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत, बड़ौत, रूड़की, सहारनपुर में महीने में कई-कई वारदात होती हैं।

श्री मूलचन्द मीणा: वहां राज तो आप ही चला रहे हो।

श्री सोमपाल: सार्वजनिक कामों के जो ठेके दिये जाते हैं, उसमें जो माफिया गिरोह होते हैं, उनकी बोली बंदूक की नोक पर होती है और वह उन्हें भी हथिया लेते हैं। अब एक मुख्य मुद्दा वहां गन्ना किसानों का है। पिछले वर्ष भारत के इतिहास में सर्वाधिक गन्ने की रकम, माननीय अंसारी जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, गन्ने की दुर्गति के विषय में कहना चाह रहा हूं, पिछले वर्ष 1382 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का मिलों के ऊपर देश भर में देय था। एक समय में 1014 करोड़ रुपया केवल उत्तर प्रदेश का था। हम माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गए। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और एक आवश्यक बैठक उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त की, गन्ना सचिव की और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की बुलाई। केन्द्र सरकार के चीनी सचिव और रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी जिसमें से एक उनके डिप्टी गवर्नर थे, उन सबकी मीटिंग बुलाकर तय किया गया कि जुलाई माह में कम से कम आधी रकम अदा कर दी जाएगी और वह क्रियान्वित भी हुआ पर आज भी मान्यवर, 451 करोड़ रुपया पिछले वर्ष का देय शेष है और इस साल मिलें फिर चल पड़ी हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है तो पिछले 451 करोड़ का भुगतान कब होगा? चीनी के विषय में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसा अभागा प्रदेश है जहां 67 प्रतिशत गन्ना मिल नहीं उठा पातीं, केवल 33 प्रतिशत उठा पाती हैं और यह 67 प्रतिशत गन्ना अगर मिल नहीं उठा पाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है पर आपत्ति की बात यह है कि पिछले वर्ष मिलों ने तो 70 से 75 रुपया प्रति क्विंटल भुगतान किसानों को किया और खंडसारी तथा दूसरी पुरानी तरह की टैक्नालाजी इस्तेमाल करने वाली जो गन्ने की प्रोसैसिंग यूनिट्स हैं, उन्होंने 30-35 रुपया और इस बार दुर्गति यह है कि केवल 25 रुपया खंडसारी इकाई गन्ने का दाम दे रही है जब कि 72 रुपया सरकार ने निश्चित किया है। मिल मालिकों की तो एक लाबी है, वह तो सरकार को भी अप्रोच कर सकते हैं, अधिकारियों के पास भी जा सकते हैं, उन्होंने तो कचहरी का भी दरवजा खटखटाया और हमने एक लोकहित की याचिका लखनऊ बैंच में दायर की थी और जब उसका फैसला आया तो उन्होंने आदेश दिया कि सरकार उत्तर प्रदेश के गन्ना क्रय और नियमन अधिनियम 1953 के तहत न केवल देय राशि का भुगतान करे बल्कि उसके ऊपर साढ़े 12 प्रतिशत ब्याज जो कानून के अंदर प्रावधानित है वह दे। पर आज तक वह 451 करोड़ रुपया शेष पड़ा हुआ है और दूसरा सीज़न शुरू हो गया है। इसी तरह से केन्द्र का चीनी नियन्त्रण अधिनियम 1966 जो 1983 में संशोधित हुआ, उसके तहत भी यही व्यवस्था है। परन्तु किसी भी सरकार ने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया और क्यों नहीं किया, यह किसी ने आज तक पूछा

नहीं। जब सरकार के द्वारा बने हुए कानून को सरकार लागू नहीं करेगी तो इस स्थिति के लिए किसान कहां जाए? यह आज तक समझ में नहीं आया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले सीजन में, पिछले चीनी वर्ष में भारत में 166 लाख टन चीनी बनी है। हमारे पूरे देश में चीनी का जो उपभोग है वह 120 से 125 लाख टन है और लगभग 45-46 लाख टन चीनी फालतू बनी हमारे उपयोग से अतिरिक्त। और उसके पूर्व वर्षों का लगभग 35-40 लाख टन का स्टाक हर वर्ष हम सर्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जिसे बफर स्टाक कहा जाता है वह 14-15 या 20 लाख टन अधिक से अधिक रहता था, तो 83 लाख टन से 85 लाट टन तो पहला है और 40-50 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन इस वर्ष होने जा रहा है। हमारी यह समझ में नहीं आता कि चीनी उद्योग इस तरह से नियंत्रण में कर, घोर नियंत्रण में रखकर सरकार इसको कब तक चला पायेगी? बार-बार यह कहा गया है कि इसको लाइसेन्स से मुक्त किया जाये क्योंकि जब तक चीनी मिल और किसान दोनों में उपबन्ध हो कर के यह निश्चय नहीं हो कि इसका क्षेत्र कैसे निर्धारित होगा तब तक इस उद्योग को नहीं चलाया जा सकता। यह अनसस्टेनेबल हो गया। परन्तु कोई सरकार इसमें हाथ डालना नहीं चाहती। सबसे अधिक नियन्त्रित अगर कोई उद्योग भारत में है तो वह चीनी का है। उसमें 20-21 उसकी गतिविधियां हैं। चीनी मिल कहां लगेगी? ....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप वह नहीं बताइये।

श्री सोमपाल: जी, उसकी क्षमता कितनी होगी, सीरा, गन्ने के दाम, चीनी के दाम, उसकी लेवी का अनुपात और जो फ्री सैल की शुगर है उसको कब छोड़ा जाएगा और उसका क्या दाम होगा ये सारी बात, सब कुछ नियंत्रित है। मैं समय अभाव के कारण सबकी गणना नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इससे अपनी जान छुटानी चाहिए और इसको लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। एक चीनी उद्योग ही ऐसा है जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध है। 1932 में अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था, अपने पिट्ठुओं के निवेश संरक्षण के लिए और अंग्रेजों द्वारा चीनी उद्योग में किए गए निवेश के संरक्षण वाली वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था आज तक लागू है। खण्डसारी उद्योग में चार से पांच प्रतिशत रिकवरी होती है, चीनी मिलों में दस से ग्यारह प्रतिशत और एक अनुमान के अनुसार यदि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की छूट दे दी जाए खण्डसारी को तो जो ग्रामीण उद्योग है, जो लघु उद्योग है जिसको प्राथमिकता देने का ढिंढोरा पचास वर्ष से पीटा जा रहा है तो 18 से 22 लाख टन चीनी अतिरिक्त बन सकती है इतने ही गन्ने से जितना आज पैदा होता है। इतनी अन्यायपूर्ण व्यवस्था और इतनी भारी वेस्टेज है इसको मैं क्रिमीनल वेस्टेज कहता हूं, केवल इस नीति, निर्णय के कारण यह हो रहा है। उसके कारण सरकार को हर पांचवे, छठे वर्ष म चीनी आयातित करनी पड़ती है बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय करके। और इसको लाइसेन्स से, अध्यादेश से, इन सब रूकावटों से, प्रतिबन्धों से सीरे को मुक्त कर देना चाहिए और गन्ने का जो भुगतान शेष है पिछले वर्ष का और इस वर्ष का वह तुरन्त किया जाना चाहिए ब्याज के साथ।

सिंचाई की व्यवस्था में नहरों का कमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 1966 से लेकर आज तक एक तिहाई रूक गया है। किसी टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंचता है, किसी पटरी का रख-रखाव नहीं है, जितनी उसकी मुख्य वाहिकाएं हैं या उप वाहिकाएं हैं, सबके अन्दर सिल्ट जमा हुआ है, रेत जमी हुई है और उनकी कभी खुदाई नहीं होती है। मुझे याद है ब्रिटिश टाइम से 1966 तक मेरे खेत में पानी आता था और मेरा क्षेत्र भी पूर्वी यमुना कैनाल के कमान क्षेत्र में स्थित है, लेकिन 1966 से लेकर आज तक एक बूंद पानी वहां नहीं गया है, कोई उनका रखरखाव करने वाला नहीं है। जबकि उसी के समकक्ष, उसी के समानान्तर हरियाणा में जो पश्चिमी कैनाल की व्यवस्था है उसका उन्होंने अत्याधुनिकीकरण किया है और तब से उसकी जल वहन क्षमता का हिस्सा वे 9.2 ले रहे हैं और हम 1.8 ले रहे हैं जबकि हमारा जो मूल फैसला था वह था कि सात इकाई वह लेंगे और चार इकाई हम लेगें। उसको हम इसलिए नहीं ले पाते कि उनकी इतनी क्षमता नहीं है। जल की चोरी होती है और जितनी हमारी नहरें हैं उनमें रिसाव के कारण बड़े-बड़े भू-भाग जल प्लावित हो चुके हैं, उनकी लाइनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां से आगे पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, ट्यूबवैलों के लिए दो घंटे से लेकर चार घंटे बिजली आती है और कई बार तो कई-कई दिन तक बिजली नहीं आती है।

पहले समय-चक्र स्थापित किया गया था जब माननीय चौधरी चरणसिंह जी मुख्य मंत्री थे और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1980 में समय-चक्र

स्थापित किया था। आपको भी याद होगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध रहे हैं। एक समय चक्र स्थापित किया गया था कि गांव के इस समूह में फला-फलां दिन बिजली आयेगी और उसके तीन चक्र बनाये थे 24 घंटे में आठ-आठ घंटे के दो से दस बजे, रात के दस बजे से दो बजे और फिर दो बजे से दिन के दस बजे तक। आज वह समय चक्र नहीं है। एक ही बार बिजली आती है, उसके ऊपर इतना अधिभार हो जाता है या तो लाइनें जल जाती हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। ट्रांसफार्मर जलने की पिछले एक साल में करीब 117 शिकायतें हैं। मैं पिछले एक साल में गवर्नर को कई चिट्ठियां लिख चुका हूं उनमें से केवल पांच या छः ही बदले गये। वे सारे ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और किसानों के खेत सूख रहे हैं। कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसलिए यह समय-चक्र पुनः स्थापित किया जाना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): समाप्त करिये।

श्री सोमपाल: मान्यवर, केवल दो-तीन मिनट और लूंगा। असंवैधानिक कनक्शन्स लगे हुए हैं, उद्योग बिजली की चोरी कर रहे हैं, बिल कोई भरता नहीं है। हमारे यहां एक किसान नेता माननीय टिकैत महोदय रिपोर्ट ही नहीं करने देते हैं किसी को और सारी सरकारें उनसे डरती हैं। इतने अवैध कनेक्शन बिजली के कहीं भी देश भर में नहीं है जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तथा इनकी कोई जांच करने को तैयार नहीं है। हमने सरकार से कई बार यह कहा कि आप दरें मत घटाइये लेकिन उनके कनेक्शन्स को वैध कर दीजिये तथा माफी की घोषणा कर दीजिये कि जो अपने आप आकर वालियंटर करेगा, स्वेच्छा से यह बात कहेगा कि हम कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसको आगे से बिल भेजना शुरू कर दें पर किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती।

सड़कों की स्थिति मैं बता चुका हूं। बेरोजगारी का ये हाल है, मेरा छोटा सा गांव है जहां पहली बार 1953 में पुलिस आई थी किसी केस के सिलसिले में। आज वहां 169 हथियार, तो जनता की जानकारी में, लोगों के पास अवैध, बिना लाइसेंस के हैं। सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यही हाल है। इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। औद्योगिकीकरण की प्रगति तो ठप्प है, जो पहले थी उनकी भी दुर्गति हो रही है। उर्वरकों के विषय में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि डी ए पी के ऊपर हमने 92 रुपये दाम घटाने की घोषणा की थी। वह घोषणा उस समय की थी जब उर्वरक की आवश्यकता नहीं थी। आज जब गेहूं की बिजाई के समय उर्वरकों की आवश्यकता पड़ी तो 62 रुपये दाम ऊपर हो गये और किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसकी उपलब्धता कहीं बनी रहे।

प्रबन्ध की दृढ़ि से मान्यवर, यह प्रदेश बहुत बड़ा है। मैं आज इस सदन के सामने माननीय सदस्य श्री सिब्ते रजी साहब का समर्थन चाहता हूं, हाई कोर्ट की बैंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए की जाती है, अकेले मेरठ सहित जो हमारे तीन मंडल हैं वे इलाहाबाद न्यायालय में जाते हैं बाकि 30 प्रतिशत में सारा उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र में आपने तीन या चार न्यायपीठों की स्थापना कर दी, राजस्थान में दो या तीन की कर दी और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश जैसा है जिसमें 15 करोड़ के करीब लोग रहते हैं वहां मेरठ में आज तक एक न्यायपीठ की स्थापना नहीं कर पाई है। पहले जब हम यहां केन्द्र सरकार को कहते थे तो यह कहा जाता था कि राज्य सरकार संस्तुति नहीं करती। आज राज्यपाल के शासन में यह बहाना भी चलने वाला नहीं है। पता नहीं क्या रुकावट है कि मेरठ में या किसी भी जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमें कोई मेरठ के विषय में न दुराग्रह है न पूर्वाग्रह, कहीं भी स्थापित कर दें। इस प्रदेश के उत्तराखंड के बंटवारे की बात हुई, वहां की विधान सभा ने संकल्प पारित किया, केन्द्र सरकार ने घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की कि उत्तराखंड देना चाहिये, मैं समर्थन करता हूं। परन्तु मैं सरकार का ध्यान और इस सदन का ध्यान इस पुरानी मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश को पांच भागों में बांट देना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): समाप्त करिये।

श्री सोमपाल: मैं चाहूंगा कि आप इसको पांच भागों में बांटें उत्तराखंड, पूर्वांचल, बुन्देखंड, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उनके नाम चाहे कुछ भी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग पुरानी है। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में सन् 1955 में एक आयोग गठित हुआ था। जब जस्टिस फजल अली को ओरल एविडेंस दी गई, 95 विधायकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लिखकर भेजा था जिसमें आपके पिताश्री बनारसीदास गुप्ता जी थे, माननीय अखिलेश जी ने यह मांग की थी। उस समय यह तय हो गया था कि करेंगे।

जस्टिस फजल अली ने अपनी संस्तुति बदल दी पर सरदार के० एन० पणिक्कर ने 9 पृष्ठ का नोट आफ डिसेंट, विमत की अपनी टिप्पणी दी और उसमें यह मांग मान

ली गई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। मेरा निवेदन है कि अगर इस मांग को पूर्ण नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति हो जाएगी, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि यह प्रदेश प्रबंध के लायक है ही नहीं।

महोदय, इन दो मांगों के साथ अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण हम देखें तो यह सिद्ध करते हैं पहले यह दलील दी जाती थी कि छोटे राज्यों की वाइबेलिटी नहीं होती, यह इससे थोथी हो गई है। निर्विवाद रूप से अब यह बात तय हो चुकी है कि अगर छोटा राज्य होगा तो प्रगति अधिक सूचारू रहेगी, ज्यादा गतिशील रहेगी। मान्यवर, इसके साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि यह सरकार चलानी है और वहां जैसी भी व्यवस्था है उसे चलाना ही है। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती मालती शर्मा: महोदय, माननीय सोमपाल जी ने सारा भाषण बजट के अगेंस्ट दिया है और हमारे फेवर में दिया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इधर आकर बैठें।

श्री सोमपाल: मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं, इस सदन के सभी पक्षों और सभी दलों से आग्रह करता हूं कि जो बात मैंने कही है उसके ऊपर वह गंभीरता से विचार करें, मन से विचार करें और इन समस्याओं का सामूहिक हल निकालने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे उत्तर प्रदेश के बजट पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया। हमारे एक साथी ने इस बजट को घाटे का बजट कहा है। लेकिन सच तो यह है, जो प्रतिलिपि हमें दी गई है उसके रिवाइज्ड एस्टीमेट में 241.61 करोड़ रुपयों का सरप्लस दिखाया गया है और इन नौ महीनों के बजट के बाद जो आखिर के तीन महीनों का बजट है, 1996-97 का, जो 31 मार्च, 1997 को खत्म होगा उसमें 23.37 करोड़ का सरप्लस शो किया गया है। ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): समय कम है आप अपनी बात कहिए।

श्री खान गुफरान जाहिदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मकसद यह है कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): समस्याओं पर आ जाइए।

श्री खान गुफरान जाहिदी: .... जब बजट में इस तरह का सरप्लस शो होता है, जिस तरह से इसमें शो किया गया है—आप इस मामले में काफी ज्ञान रखते हैं, इसमें आपका दखल भी हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि बजट स्टैटिक है, इसमें हरकत का, मुतहरिक का कोई थ्रस्ट नहीं है। इस पूरे बजट को पढ़ने के बाद, इसके सारे आंकड़े देखने के बाद इसमें साफ जगलरी नजर आती है। एक रूपये में से जो 80 पैसा खर्च हो रहा है वह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज पर खर्च हो रहा है। सारी सर्विसेज में, चाहे वह एकानामि सर्विस हो, चाहे सोशल सर्विस हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो चाहे, ट्रांसपोर्ट का टैक्स लेना हो और चाहे वह टैक्स एरिया हो या नान-टैक्स एरिया हो, 80 पैसा सरकार को चलाने में निकल रहा है और केवल 20 परसेंट डेवलपमेंट के लिए रह गया है। नतीजा यह है कि यह खींचतान का बजट है और यह बजट आंकड़ों को पूर्ण करके यहां पर रख दिया गया है, इसको देखने से यह साफ जाहिर होता है। महोदय, पहले ही स्टेटमेंट से साफ जाहिर हो जाता है कि यह बजट स्टैटिक बजट है और इसमें किसी तरह का कोई मोशन, मोबलिटी और हरकत डेवलपमेंट की तरफ नहीं है। नतीजा यह है और मैं आनरेबल मेंबर सोमपाल जी से एग्री करता हूं कि... लेकिन इतना नहीं एग्री कर सकता हूं कि जब जब छोटी छोटी पार्टियों की सरकारें बनीं, जल्दी जल्दी सरकारें गिरीं, विकास ठप्प हुआ है, मैं उनके इस तर्क से अपने को करीब नहीं पाता। सच यह है कि अलायेंसेज़ का ज़माना ज़रूर आ गया है तो अलायेंसेज़ के मौके पर भी अलायेंस का न बनना, जिसको खुद आपको करना-धरना, केन्द्र सरकार को देखना, इसका दोष ठीक केन्द्र की 13 साथियों की मिली हुई सरकार पर है। उन्होंने देश में अलायेंस की सरकार होने के बावजूद भी अलायेंस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने में आज तक साथ नहीं दिया और कोई रास्ता नहीं निकाला। इसकी जिम्मेदारी छोटी पार्टियों पर नहीं है बल्कि उस पार्टी पर है जो उन सब में बड़ी है। अब मैं बजट के दूसरे हिस्सों पर आना चाहता हूं। राजनीति के उन सवालों पर जिन पर हमारी माननीय सदस्य सिब्ते रज़ी साहब ने रोशनी डाल दी है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं और बजट का समर्थन करता हूं लेकिन, यह लेकिन भी बड़ा अजीबोगरीब है, मान्यवर, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हों, स्कूल बनाने हों, इसमें बड़ा साफ दिया है

हमारे बजट में इनक्रीज़ इन एक्सपेंडीचर आन एजुकेशन, हैल्थ, फेमिली वेलफेयर, सोशल सिक्युल रिटी स्कीम के नाम पर निल, यानी पिछले दो-तीन सालों में कोई बेवा नहीं हुई, कोई बूढ़ा नहीं हुआ, छात्रवृत्ति गायब। 68 जिले हैं और इनमें से 38 जिले रात के 6 बजे से अंधेरे में डूब जाते हैं। जैसे कि सोमपाल जी ने कहा है, जो समय चक्र, रोस्टर बना हुआ था, वह पिछले चार-पांच साल में जो सरकारें आई हैं, अब यह तो फिर उधर जा रहा है, मैं क्या करूं, मेरे साथी हैं, सहयोगी भी हैं, लेकिन यह रोस्टर रोस्ट हो गया बिजली घर में। कोई रोस्टर नाम की चीज नहीं है। डकैतियां इसीलिए बढ़ रही हैं, शहर घपाघप अंधेरे में है। पिछली सरकार ने, पिछला भी प्रेज़ीडेंट रूल था और अब फिर प्रेज़ीडेंट रूल है चल रहा है तो पिछले प्रेजीडेंट रूल में यहां पर महिलाओं के सिलसिले में एक्ट आने जा रहा था, बिल पेश हो रहा था। लड़कियों की तालीम पर, चाहे यह पक्ष हो या यह पक्ष हो पूरे हिन्दुस्तान में जायज़ा हुआ कि लड़कियों की तालीम के लिए डिग्री स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडियेट कालेज स्पेशली जिलों में खोले जाएं हमारे यहां भी लिया गया। 890 ब्लाक हैं, इनमें लड़कियों के स्कूल खोलने की बात की गई। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब, यह सब कागज़ पर तैयार हो गया, उच्च स्तरीय मीटिंग एजुकेशन की बैठ गई, फैसले हो गये कि 38 ब्लाकों में यह स्कूल कायम किये जाएंगे। उसमें हमारा जिला, बैकवर्ड जिला फतेहपुर भी है, अभागा है, उसमें उच्च स्तरीय मीटिंग होने के बाद भी किसी ब्लाक में आज तक एक भी स्कूल के लिए एक नया पैसा नहीं दिया गया। दो-दो साल से स्कीमें चलती हैं, उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही हैं, कागज़ात जा रहे हैं डी०आई०एस० के पास, बी०आई०एस० के पास, यह कहते हैं कि एजुकेशन पर इनक्रीज हो गया है लेकिन फिर भी बजट का समर्थन करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट और रोडवेज की हालत देख लें। हमारे यहां रोजवेज़ चलती हैं यहां पर ब्लू लाइन इसलिए बंद कर दी गई कि यह कत्ल करती है, सड़क पर चलने वालों को मारती है। हमारे यहां रोडवेज़ चलती है, सड़कों पर पता नहीं कैसे चलती है। ऐसी शानदार रोडवेज़ कहीं पर नहीं होगी। बस की हर चीज़ बोलती है लेकिन नहीं बोलता तो हार्न नहीं बोलता। यह अजीब हालत है। सड़कें जर्जर, रोडवेज़ का निज़ाम खराब और सेंटर से जो अस्सिटेंस मिल रही है जिसका हमारे माननीय साथी आनरेबल सिब्ते रज़ी साहब ने जिक्र किया।

माननीय नरेन्दर मोहन जी ने कहा। हम समझते हैं कि सेंटर के असिस्टेंस से ये जो काम हैं ये पिछले 6 महीने या साल भर से रुके पड़े हैं। हमारे यहां तो फतेहपुर में एक ओवर ब्रिज बन रहा है। मेरा ख्याल है कि ओवर 12 इयर्स ओल्ड है।

श्री नरेन्द्र मोहनः कितनी साल से बन रहा है।

श्री खान गुफरान जाहिदीः 12 साल से ऊपर से।

छोटे शहर, इंटरमीडिएट सिटीज में कोई ओवर ब्रिज नहीं और कहीं एक एक कारपोरेशन, सिटी में दस दस ओवर ब्रिज। यह कितना अनबैलेंस्ड है। किसी तरह से प्रोग्रेस हो रही है। मैं तीन बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा।. ...**(व्यवल धान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप इधर ही कहिए।

श्री खान गुफरान जाहिदीः मैं आप ही की तरफ मुतवज्जह हूं। जो कुछ भी कहूंगा वह आपके माध्यम से ही कहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जी हां, मौका मिलेगा उनको।

श्री खान गुफरान जाहिदीः हमारे यहां आयुर्वेद का घोटाला हुआ— बड़ा भारी। वहां चारे का हो गया तो यहां आयुर्वेद दवाइयों का हो गया। बात खुलेगी। अभी तो अदालतों तक है। जब मामला है तो खुलेगा, जो भी मामला हो लेकिन इतनी बात आपसे कह सकता हूं कि एक नहीं अनेक हैं— इन्फारमेशन डिपार्टमेंट लीजिए, पी०डब्ल्यू०डी० डिपार्टमेंट लीजिए, फारेस्ट डिपार्टमेंट लीजिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछली सात पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आप नहीं कोई और थे, और उसके बाद भी उसका सिलसिला शुरू रहा और स्टेट के बजट में उसका प्राविजन होता रहा — पेड़ लगाने का। अगर वे सब पेड़ लग गए

होते मारटैलिटी रेट को शामिल करके तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी सड़क पर चलने की नौबत ही नहीं आती। सेक्रेटेरिएट में ही कोई जगह बाकी नहीं रहती। ये आपके घोटाले हैं। हर डिपार्टमेंट के है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इस तरह न हो। मान्यवर, 419+1 कहकर आज विधायक है वहां। नहीं कहना चाहता हूं वह फिगर। इसलिए कि उसी फिगर के आने से, उसी वजह से वह असेम्बली ही नहीं बुलाई जा रही है। 419+1 कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज हम यहां पर 10-15-20 साथी बैठकर उत्तर प्रदेश के बजट पर अपनी राय दे रहे हैं और 890 ब्लाकों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, जो हमारे विधायक साथी हैं, चाहे वे किसी दल के हों, किसी वर्ग के हों, ऊंची सीढ़ी से आए या नीची सीढ़ी से आए, उनके क्षेत्रों के अन्दर क्या हो रहा है? विकास ठप्प है। किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। एजूकेशन का दावा है, एजूकेशन की हालत मैंने आपको बता दी। बिजली का दावा है, बिजली की हालत मैंने आपको बता दी। रिकवरी रेट 35 परसेंट से जिस मुल्क में बिजली का कम हो, जिस बोर्ड का हो वह बोर्ड तो ठीक बैठेगा ही नहीं, वह तो जल जाना चाहिए था लेकिन आपके बजट से जो प्राविजन बराबर हुए जा रहे है वे खत्म किए दे रहे हैं? लेकिन प्रायवेटाइजेशन के नाम पर चीनी बेचनी चाहिए। प्रायवेटाइजेशन के नाम पर सूती मिल चलने के लिए जो बनाए गए थे किसी जमाने में, इन्सटेड आफ इम्प्रूविंग देम आपको उनको बेच दें और बिचौलियों के दे दें। आज में समझता हूं कि सबसे ज्यादा परेशानी का आलम यह है कि किसान को अगर गेहूं के दाम उतने मिल जाएं जो आज मारकेट में खाने वाले को देने पड़ रहे हैं तो उससे बड़ा रईस कोई नहीं हो सकता। लेकिन 15 रुपए में कौन बेच रहा है? 10 रुपये में आटा कैसे बिक रहा है? मेरा कहना यह है कि न तो किसान को पैसा मिला और खरीददार भी जब्र हुआ और फायदा हुआ है उस मिडिलमैन का, ब्रोकर का जो मुल्क में छाये जा रहा है। आज ब्रोकर होर्डिंग कर रहा है, लोगों को भूखा मार रहा है। रायट्स होने का खतरा है जैसे कि भोपाल, मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं।

मान्यवर, एक बात कहूंगा जो बहुत जरूरी समझता हूं वह यह कि अब चार चार बार प्रेजीडेंट रूल लग रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि यह बजट क्या इसी तरह अफसरों का होगा। बिल्कुल सही कहा है किसी साथी ने कि यह अफसरों का बनाया हुआ बजट है। जब छोटी-छोटी पार्टियों की सरकारें बराबर टूटती हैं तो अफसरशाही की ताकत बढ़ती है। यह अफसरशाही, उनकी इजारेदारी भी उत्तर प्रदेश को इतनी खराब सूरतेहाल में पहुंचाने में एक हिस्सेदार है इसमें दो राय नहीं हैं। इसलिए कि उन पर कोई पोलिटीकल अंकुश नहीं है। उन पर कोई दबाव नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपसे, आज फाईनांस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं और उनके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर की बात कहना चाहता हूं कि प्रेसीडेंट रूल जब 356 में लगे तो आप यह बजट जरूर पास करें क्योंकि आपकी मजबूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ एक सुपरवाइज़री कमेटी जरूर बननी चाहिए। मुख्तलिफ पार्टियों के ज्यादा से ज्यादा मैंबरों को लेने के बाद पार्टी से ऊपर उठकर एक फैसला लिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैंबरान उसमें शामिल हों उस प्रदेश के और वे फैसला ले सकें। कोई अंकुश वहां के अफसरों की इज़ारादारी पर जरूर लगना चाहिए और वह एक अलाहिदा स्टडी कमेटी बनाना चाहिए। यह मेरा प्रोपोज़ल है मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम साहब इस पर जरूर गौर करेंगे कि एक स्टडी ग्रुप एक तरीकेकार बनाया जाए, एक सुपरवाइज़री बॉडी जरूर बनाई जाए, मैंबरान-ए-राज्य सभा पर हो, मैंबरान-ए-लोक सभा पर हो, मुख्तलिफ पार्टियों के उसमें नुमाइंदे लिए जाएं और वे कम से कम 356 के उस पीरियड में जब वहां प्रेसीडेंट रूल हो, तो इसकी निगरानी जरूर करें। यह एक बहुत इंपार्टेंट इश्यू बन जाता है। इसलिए कि 419 प्लस वन को तो मौका मिल नहीं रहा है, कम से कम 50 आदमियों को, सौ आदमियों को यह मौका जरूर मिल जाए कि वे बैठकर अपने सूबे के बारे में गौर कर सकें और समझ सकें तथा कोई राय दे सकें और आप सुपरवाइज़री हैसियत में उस राय को, उस राष्ट्रपति के नुमायंदे को, जो वहां हमारे आज हाकिम-ए-आला हैं और जो वहां की सरकार चला रहे हैं, वह कुछ फैसला ले सकें और कुछ काम हो सके। डेक्लेरेशन ऐसे न किए जाएं जब तक कि बजट में प्रोविज़न न हो, जब तक कि उसे विधि सेक्रेटरी के हाथ से पास न कर दिया जाए। तो यह धोखे से, कभी महिला बिल का एनाउंसमेंट हो गया। वोट पड़ने वाले थे, महिला बिल के नाम पर वोट

दे दिया। जब वह शैल्व हो रहा है। कभी उत्तराखंड का एनाउंसमेंट हो गया लाल किले से, वोट पड़ गए। साथ नहीं आया। वह भी शैल्व कर दो। कारखाने लगाने के लिए आपने वहां पर लगा दिया कि यहां पर बहुत बड़ा सैन्ट्रल गवर्नमेंट का कारखाना लगेगा। माननीय, उपसभाध्यक्ष जी, पत्थर लगाए जाएं, पत्थर मारे न जाएं, पत्थर उखाड़े न जाएं। जो चीज़ की जाए, जो फैसला वहां की जनता को जो एतमाद में लिया जाए तो उसका काम किया जाए। क्या हकीकत नहीं, माननीय सदस्य गन्ने के सवाल पर बोल रहे थे, क्या यह हकीकत नहीं कि 1979 में चीनी मिल मालिकों ने एक रिट की थी और रट पर की थी। उस जमाने का पैसा आज तक नहीं चूंकि हाई कोर्ट और मैं तो उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। इंटरीम आर्डर हो गया कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगा। 1979 से सैकड़ों-करोड़ों रुपया वह पड़ा हुआ है। मान्यवर, अभी तक पड़ा हुआ है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि गन्ना काश्तकारों का 1979 का पैसा तो अलग और 62 का अलग, और यह मुसलसल पैसा बाकी चला आ रहा है। यह पैसा कौन रोके हुए हैं? अदालतों के फैसले होते हैं उसके लिए हमारे वकील वहां लगते हैं। उनका काम है कि वे फैसले को ठीक कराएं और कम से कम अब इस तरह के फैसले हों तो यह भी रेक्वेस्ट की जाए कि आप फैसला चाहे जब करें, उनका बकाया कुछ भी करें लेकिन उसका कुछ पोर्शन किसानों को दें ताकि वे अपनी जीविका चला सकें।

आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सोशल सैक्योरिटी की स्कीमों पर, छात्रवृत्ति पर, एजुकेशन की स्कीमों पर जो पैसा दिया है उसको सुनिश्चित कराया जाए और यह देखा जाए कि अगली मर्तबा हम इस तरह से बजट को न करें और कोई एक अवामी सरकार वहां पर बन कर आ जाए, इसके लिए हम इस तरफ के साथियों के खास तौर पर उन लोगों से जो सब मिल कर 240 और 245 के ऊपर पहुंचते हैं उनका यह हक बनाते हैं और यहां की मरकज़ी सरकार पर यह पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह एक गैर फिरकापरस्त सरकार के बनाने में जिस पर हमने जो मैं यहां हाजिर हो गया हूं, एक बड़ी सरमायेदार तोप को हराकर आया हूं, इसलिए मैं यह समझता हूं कि बेहतर रास्ता यह है कि अवामी सरकार के बजट पर हम यहां से कोई टिप्पणी न कर सकें और वहां के लोग भी अपनी जिम्मेदारी और अपना एतमाद लेकर वहां की भलाई के लिए कुछ विकास कर सकें, जो आज पूरी तरह ठप्प है। मैं बजट का फिर भी सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: How long are we going to sit here, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): We will take up the Half-an-Hour Discussion at 6 o'clock.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: No, Sir. We can take it up tomorrow. There is no hurry. Today there was no lunch break also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You know that the Upper House sometimes works harder.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Kindly consider it, Sir. We can take it up tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): We will see at 6 o'clock. Shri Raj Nath Surya.

श्री राजनाथ सिंह सूर्य (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, नरेन्द्र मोहन जी ने जो बातें कहीं हैं, मैं उन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सिब्ते रज़ी, माननीय सोमपाल जी और माननीय गुफरान जैहदी जी का जो पूरा भाषण है, उस की अंतिम पंक्ति को छोड़कर बाकी सब का मुझे ही समर्थन करना पड़ेगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी: यह आप की मजबूरी है।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: हमारी भी मजबूरी है और श्रीमन् इस मजबूरी का एक कारण है कि इस सदन का जो तीन-चौथाई हिस्सा है, वह सब एक साथ है।

श्री ईश दत्त यादव: कम-से-कम यह तो मान लिया आप ने।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: हां, मान रहा हूं और कैसे साथ हैं, यह भी बता देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी): आप चैयर को सम्बोधित करिए तो थोड़े समय में बहुत सी बातें कह पाएंगे। ईश दत्त जी तो आप का ध्यान बंटा रहे हैं।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: वह जान बचा नहीं पाएंगे। श्रीमन् कैसे साथ हैं, इस की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। श्रीमन् एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग जिस को पक्षी भी

कहते हैं और जानवर भी कहते हैं। वह भागता भी है और उड़ भी लेता है। फिर भागते-भागते जब वह थक जाता है तो अपने बचाव के लिए अपने सिर को बालू में छुपा लेता है और समझता है कि मेरा शिकार नहीं हो सकेगा। हमारे कांग्रेस के जो भाई बैठे हैं, और मित्र बैठे हैं जोकि अर्जियां लगा रहे हैं, वह लोग उसी स्थिति में हैं। वह समझते हैं कि किसी-न-किसी दिन तो हमारी अर्जी लग ही जाएगी। अरे भाई, अर्जी लगाना छोड़िए और मर्जी की बात कीजिए क्योंकि राजनीति में अर्जियों से बहुत कुछ काम नहीं होता है। श्रीमन् अभी गुफरान साहब ने दावा किया कि वह बड़ी तोप को गिराकर और जम्हूरियत को चार चांद लगाने के लिए सेकुलर फोर्सेस की एक संगठित शक्ति का प्रतीक बनकर यहां आए हैं। श्रीमन् मुझे बचपन में सुना हुआ एक किस्सा याद आता है। एक गांव था जिस में सब एक प्रकार के लोग थे। सब की नाक कटी हुई थी। उन में एक नाक वाला पहुंच गया तो लोगों ने कहा कि देखो, नकटू आ गया। तो हम लोग तो नकटू हैं। नककटों में तो हमारी गिनती हो नहीं सकती और नकटू की स्थिति तो हम अपनी बरकरार रखेंगे, लेकिन जो आप सब हैं जोकि नाक कटाए हुए हैं और एक साथ हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इला अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप सब मिलकर कम-से-कम एक सरकार बना लीजिए। सिब्ते रज़ी साहब ने भी वह ऐना रोया, गुफरान साहब ने कहा और सोमपाल जी भी कह रहे थे, तो सब मिलकर बना लीजिए। नकटू को छोड़कर आप जितने लोग हैं, वह सब लोग मिलकर बना क्यों नहीं लेते। धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक क्यों नहीं हो जाती हैं? एक साथ खड़ी क्यों नहीं हो जातीं? फिर श्रीमन् सब ने मिलकर किस के हाथ में उत्तर प्रदेश का शासन दे रखा है, उस के बारे में मेरे लिए कोई राय देने की जरूरत नहीं है। सिब्ते रज़ी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश का शासन राजभवन में बंद हो गया है। अब यह स्थिति प्रदान करने का काम किस ने किया है? शायद सिब्ते रज़ी साहब को मालूम नहीं हो, शासन कभी-कभी राजभवन से निकलता है, जब उस की गोल्फ खेलने का इरादा होता है। पूरे प्रशासन को लेकर नैनीताल चला जाता है गोल्फ खेलने के लिए। वहां जब गोल्फ खेलते-खेलते प्रशासनिक मुखिया बीमार हो जाता है तो फिर उस को लाकर एस्कॉर्ट में भर्ती कराना पड़ता है और फिर वह पड़े-पड़े बंद हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन राजभवन से कभी-कभी निकलता है तो गोल्फ खेलने के लिए निकलता है।

श्रीमन् बजट के प्रावधानों की जो बातें की गयी हैं, जिक्र नहीं किया है वह यह है कि हमारा वहां का पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र इस समय महाभ्रष्टों की पहचान करने में लगा हुआ है. जहां कि इस प्रकार की स्थिति है, डीक्रेट बेलेट के आई०ए०एस० अधिकारी अपने बीच से महाभ्रष्टों की पहचान करने में लगे हुए हैं, उस प्रदेश का प्रशासन कैसी स्थिति में होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है.

श्रीमन् 1947 या उससे पहले से, हम तो केवल डेढ़ साल शासन में रहे हैं बाकी सारा समय तो उधर के बैठने वाले शासन में रहे हैं, जो कुछ दिशा दी है, वह उधर के ही बैठने वालों ने शासन को दिशा दी है औ उस दिशा का परिणाम यह है कि आज वहां का सरकारी अधिकारी बिल्कुल कर्त्तव्य-परायण नहीं है. आज वहां का सरकारी अधिकारी कितना कर्त्तव्य-परायण है, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं. 6 दिसम्बर को लखनऊ मेल दिल्ली से लखनऊ जा रही थी, मुरादाबाद से पहले वह ट्रेन डिरेल हो गई, उसके 11 डिब्बे पटरी से उतर गए. वहां के जिलाधिकारी को, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, रात के 3.00 बजे यह सूचना दे दी गई, टेलीफोन उस स्थान पर लग गया था उसके द्वारा, कि ऐसे-ऐसे ट्रेन डिरेल हो गई है और, श्रीमन्, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबेरे 8:00 बजे जब हम मुरादाबाद स्टेशन पर पहुंचे, रेस्क्यु ट्रेन के ज़रिए, तो वहां केवल एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर और एक ए०जी०एम० मौजूद था, इसके अलावा दुर्घटना-स्थल पर एक भी आदमी मौजूद नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का चयन ज्येष्ठता, श्रेष्ठता या पात्रता के आधार पर होने के बजाए उपादेयता के आधार पर किया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों के हाथ में अगर हम सारा बजट देंगे तो इसका क्या स्वरूप बनेगा? आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि विधायक चुनकर आए है, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वे अपना बजट पास नहीं करा पाते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं? भई, आप जो नकटुओं के अलावा लोग हैं, उनकी तो संख्या इतनी है ही कि सरकार बना सकते हैं, तो मिलकर के सरकार बना लीजिए। आप विधायकों के हाथ से यह पहल क्यों छीन रहे हैं?

श्रीमन्, हमारे प्रधान मंत्री जी जुलाई में उत्तर प्रदेश में गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि गोरखपुर का खाद कारखाना तीन महीने में चालू करा दिया जाएगा। अब पता नहीं उनको मालूम था कि नहीं कि कितने दिनों से

यह कारखाना बंद है, इसकी स्थिति क्या है, चालू हो सकता है या नहीं, उन्होंने घूमकर नहीं देखा। मऊनाथ भंजन गए तो उन्होंने कहा कि बुनकरों को बिजली में छूट दे दी गई है, किसानों को बिजली में छूट दे दी गई है और 10 रुपए प्रति हार्स पावर की छूट देने की घोषणा कर दी गई। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड की स्थिति आज यह है कि हमारा जो एक ऊंचाहार का पावर हाऊस था, वह सैंट्रल बोर्ड ने अपने हाथ में इसलिए ले लिया है क्योंकि हम उसका कर्जा नहीं दे सकते थे। आनपारा का हमारा जो विद्युत केन्द्र है, उसके उत्पादन प्रभावित हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय जितने हमारे संयंत्र लगे हुए हैं उनमें उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है। राजधानी और कुछ प्रमुख स्थानों को छोड़कर बाकी स्थानों पर ठीक प्रकार से बिजली नहीं आ रही है।

अब इसका कारण यह है कि विकास के लिए जो नीति निर्धारित होनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करने के बजाय हाथी के पांव जगह-जगह खड़े कर दिए जाते हैं। कभी अमेठी होता है, कभी इटावा होता है, कभी कोई और स्थान होता है। इसके कारण उत्तर प्रदेश का सम्यक विकास संभव नहीं हो पाता है। अभी पुलिस पर खर्च की बात के संदर्भ में कहा गया है कि इसको बढ़ाया गया है पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी जो सीमा नेपाल से लगी हुई है, वहां से बहुत तस्करी हो रही है, हथियार आ रहे हैं और इसके बारे में यहां वक्तव्य भी दिए गए हैं लेकिन उनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके लिए अभी तक उचित प्रबंध नहीं किया गया है। चौकियां स्थापित करने का निर्णय 1985 में लिया गया था लेकिन आज तक वे चौकियां स्थापित नहीं हो पाई हैं। लोग निर्बाध रूप से वहां से सामान लेकर आ रहे हैं।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए जब बहस हो रही थी तो हमारे गृह मंत्री जी ने उस सदन में भाषण करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे बड़ा रोग है, वह जातीयता का है। उत्तर प्रदेश में जातीयता की राजनीति हो रही है। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए। अभी सोमपाल जी ने कहा था कि वे हृदय की बात कहना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिवाय इस बात को कहने के कि वे इस बजट का समर्थन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त बाकी सभी बातें उन्होंने हृदय से कही हैं। उनको यह प्रयत्न करना चाहिए कि उनके हृदय की बातों के अनुरूप यह सरकार चले, जो चर्चाएं की गयी हैं, उस में सोशल वेलफेयर के बारे में गुफरान साहब ने कहा कि कोई प्रावधान नहीं है। तो सोशल वेलफेयर क्या होता है भाई? परसनल वेलफेयर इज़ सुप्रीम. राजभवन में विशेष कक्षों को सजाने के लिए अगर 40 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, उसके डेकोरेटर को डेढ़ लाख रुपया दिया जाएगा तो आम आदमी के वेलफेयर के लिए फिर काम कैस किया जाएगा? वहां तो लाट साहब का शासन है, जो अपने बेटे को कहीं भेजने के लिए पूरा का पूरा क्षेत्र ही रिज़र्व करा देते हैं, उस क्षेत्र में कोई जा भी नहीं सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): बजट पर भी आ जाइए.

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: श्रीमन् मैं बजट पर ही बात कर रहा हूं. आखिर हम इस बजट को किसके हाथ में खर्च के लिए दऐंगे? जिस आदमी के हाथ में देंगे, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश में यह कहा गया कि विकास के लिए धन नहीं है, विकास के लिए केवल एक मद में धन है और वह है मंडी परिषद. उससे हमको जो शुल्क मिलता है, उससे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं. केवल 10-12 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 30 करोड़ रुपयों की छूट दी गई. मंडी परिषद ने उसका विरोध किया, सचिव ने, विभाग ने विरोध किया, मुख्य सचिव ने विरोध किया, राज्यपाल के सलाहकार तक ने विरोध किया लेकिन फिर भी वह छूट दी गई और अभी यह छूट धान पर, गेहूं पर और आटा मिलों पर दी जाने वाली है. तो यह बजट हम किसके हाथ में दे रहे हैं, किस व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं?

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ी खराब स्थिति है. हमारे मित्रों ने वहां की शांति-व्यवस्था की स्थिति और बाकी स्थितियों का ज़िक्र किया है लेकिन एक स्थिति का जिसका वे समर्थन कर रहे हैं। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश में हैं, जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल नहीं सकती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिम बंगाल) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से उत्तर प्रदेश के बजट पर चल रही चर्चा को सुन रही थी और सोच रही थी कि यह समस्या बची है, इस पर मैं बोलूंगी। मुझ से पहले जो 6 वक्ता बोले हैं उन्होंने करीब-करीब सभी समस्याओं के बारे में यहां ध्यान आकर्षित किया है और

राजनाथ जी ने तो गोरखपुर के खाद कारखाने के बारे में भी बोल दिया। इसलिए अब यह चुनावी भाषण और पोलिटिकल भाषण देने की जरूरत मैं नहीं समझती हूं।

महोदय, कुछ देर पहले एक सांसद मित्र ने कहा था कि जब हम सदन में भीतर घुसते है तो यह लिखा हुआ देखते हैं — "सत्यं बदा धर्मं चर"। अभी मैं परसों ही उत्तर प्रदेश गई थी, वहां एक कहावत चल रही है कि कुछ सच बोलने वालों ने धर्म को चारा बनाकर लोगों को खिला दिया; जब धर्म चर गया तो बचा कहां धर्म? इसलिए जो पहले की परिभाषा थी — "सत्यं वदः धर्म चर"। उस पर चलने वाले लोग बचे नहीं हैं।

मैं एक राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए मेरे मन में जो बातें आती हैं, मैं वही कहती हूं। मैं अपने हृदय की बात कह रही हूं कि मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि —

"खत्म हो जाती कहीं तो दास्तान,
फिर न उठती बात दोबारा यहां"

कई बरसों से मैं देख रही हूं, बातें होती हैं, बजट आता है, फिर बातें होतीं हैं, कभी प्रेजीडेंट रूल हो जाता है, कभी हट जाता है, कभी माइनोरिटी क सरकार आ जाती है लेकिन वहां जो भी हो, हमारे जो भाई उधर बैठे हैं वे अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि जब उनकी सरकर वहां थी तो उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके लिए अभी तक हमें रोना पड़ रहा है। उन्होंने क्या किया, इसका जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहती हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश के डांवाडोल राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था नहीं तो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो धारा 356 का समर्थन करता हो। वैसे मैं पश्चिम बंगाल से सांसद हूं लेकिन उत्तर प्रदेश से मेरा भावात्मक लगाव है क्योंकि मेरा जन्म आजमगढ़ में हुआ था। अभी भाई बी०बी० दत्त ने कहा कि जब भाषा अपनी हो और चर्चा उत्तर प्रदेश की हो तो आपको बहुत बोलना चाहिए लेकिन मैं बहुत नहीं बोलूंगी। राष्ट्रपति शासन वहां तभी लागू हुआ जब किसी भी दल की सरकार वहां नहीं बन पाई। अभी तो सब कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बना ली? वहां कोई सरकार बन नहीं पाई और उसका दुःख उठाना पड़ रहा है वहां की जनता को।

वहां के प्रदेश के विकास का प्रश्न हो, सड़कों के विकास का प्रश्न हो बिजली का प्रश्न हो, महिलाओं के विकास की बात हो कहीं न कहीं जनता ही इस दुख और दर्द को भुगत रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव और शहर से होकर गुजर जाएं और लोगों को पता चल जाता है कि आप सांसद हैं, विधायक हैं तो उनके पास दर्द की इतनी लम्बी-लम्बी दास्तानें हैं कि सुनने के लिए हमें इन दो कानों के अतिरिक्त और कानों की जरूरत होती है। यहां यह भी प्रश्न उठाया गया कि वहां की सड़कें बहुत खराब हैं। मैं इसकी प्रत्यक्ष गवाह हूं। सड़कें तो ऐसी हैं कि यदि कहा जाए कि सड़कों में गड्ढे हैं, तो अतिश्योक्ति हो जाएगी। गड्ढों में सड़कें हैं, गड्ढे अधिक हैं सड़कें कम हैं। एक और मजे की बात है कि जब सड़कों पर बिजली नहीं रहती और मोटर बाईक पर पति-पत्नी जा रहे होते हैं तो पति आगे निकल जाता है और उछलकर पत्नी पीछे गिर जाती है और हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। यह सच घटना है, मान्यवर। बहुत दूर जाने पर जब पति को पता चलता है कि पत्नी कहां रह गई, तो मालूम होता है कि सड़कों का आलम यह है कि वह हॉस्पिटल में पहुंच गई। **(समय की घंटी)**

आपने अभी घंटी बजादी।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जल्दी बजट पर आ जाइए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: इसलिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल और सामाजिक माहौल पर बहुत अधिक बातें करने की जरूरत नहीं है। यह जो बजट आया है इस बजट में मुझे जैसा दिखाई पड़ा मैंने इसको सरकारी निगाह से देखा। मुझे ऐसा लगा कि पर्यटन पर उत्तर प्रदेश में असीम सम्भावनाएं हैं और पता नहीं पर्यटन पर हमारी केन्द्र सरकार ने बजट 53 से 11 क्यों कर दिया है। इस पर मंत्री जी जवाब देंगे। पेंशन तथा सेवानिवृत्त लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली को ज्यों का त्यों रखा है। वहां अनेकों पेंशन होल्डर्स से बातें करके पता चला कि उन्हें उसी पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। मैं इस बजट की सराहना करुंगी। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को लेकर शिक्षा, खेल-कूद तथा संस्कृति पर बजट बढ़ाया गया है। चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर भी बढ़ाया गया है, परिवार कल्याण पर थोड़ा बढ़ाया गया है। श्रम तथा रोजगार पर भी बढ़ाया गया है। यदि शिक्षा संस्थानों की चर्चा करें तो महिलाओं के लिए अभी भी स्कूल और कालेजों की बहुत कमी है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऐसा गिरा हुआ है कि गांवों में जो स्कूल हैं उनमें बारातें ठहरती हैं, पढ़ाई नहीं होती। अगर विद्यार्थी आते हैं तो शिक्षक उन्हें खेलने के लिए भेज देते हैं। देखने वाला

कोई नहीं है कि वहां किस तरह से चल रहा है तथा कैसे उनका चयन होता है, किस तरह उनका वेतन मिलता है यह भी कोई देखने वाला नहीं है। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रक पर सरकार ने बजट में अधिक धनराशि दी है लेकिन ऊर्जा के बारे में क्यों खामोश हैं, इस पर भी कुछ कहना चाहिए था। यहां कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री नरेन्द्र मोहन: एक रुपया है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: एक तो यह टोकन है। यह ध्यान में नहीं है या उत्तर प्रदेश इतना अधिक अंधेरे में डूबा हुआ है कि प्रकाश की एक किरण की भी आशा नहीं है। मैं सरकार से इस बजट का समर्थन करते हुए प्रश्न रखना चाहूंगी कि जो इन्होंने घाटे का बजट दिखाया है उसके लिए क्या कोई सम्पूर्ति करेंगे। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): श्री मूलचन्द मीणा। आप तो विशेषज्ञ हैं बजट के। तीन मिनट में समाप्त कीजिए। समय हो चुका है, इसी मुद्दे पर आ जाइए। अभी पांच लोग और हैं।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर इधर की साईड के और उधर की साईड के जो सदस्य चर्चा कर रहे थे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इधर की साईड के कई सदस्यों ने अनेक बातें कहीं। जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हुई, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह जो खिलवाड़ हुआ तीन साल के लिए, उसके मुख्य दोषी कौन हैं—मंडल और कमंडल वाले दोनों ही दोषी हैं इसके लिए। कमंडल वालों ने उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं भरकर लोगों को भड़काया और साम्प्रदायिक दंगे कराएं। मंडल वालों ने जातिवादी भावनाएं प्रदेश के अंदर फैलाई जिसका परिणाम आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह दोनों विचार-धारा वाले लोग आज भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सोमपाल जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जनादेश इस प्रकार का था। जातिवाद का ज़हर जो आपने उस प्रदेश के अंदर घोला है, आप उसे बरकरार रखना चाहते हैं। कमंडल वाले अब धीरे-धीरे अपने कंमडल को भूलते जा रहे हैं और वहां की जनता ने सही निर्णय किया है। जनता की समझ में आया है और लोक सभा में उसने 52 सदस्य भेजे हैं लेकिन विधान सभा के अंदर उनको बहुमत नहीं दिया, इससे आप लोगों को सबक लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है उत्तर प्रदेश

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): चिदम्बरम जी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनके लिए कुछ कहिए उत्तर प्रदेश की तरफ से। यह राजस्थान का उपहार होगा।

श्री मूलचन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने कामना की थी कि आने वाले सेशन में हमें उत्तर प्रदेश का बजट पुनः पास न करना पड़े लेकिन इस सदन के सभी सदस्य यदि समझदारी से काम लेते और भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य अभी कह रहे थे, नकटू की बात कर रहे थे आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कही। आपको राज्य सभा के चुनाव में ही पता लग गया कि आपकी नाक है या नहीं है, इसके बाद भी आप नकटू की बात करें तो यह शोभा नहीं देता है। आप फिर भी बात करते हैं। एक बार नाक कटने के बाद दोबारा जोड़ कर फिर कहते हैं कि सरकार हम बना लेंगे, यह असंभव है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, जिस प्रकार आपने जनता की भावनाओं के साथ खेला है, उसके लिए आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के आंकड़े आ जाते हैं। अधिकारी अपने मन-मुताबिक जिस प्रकार विभाग में काम करते हैं, उसी तरह के आंकड़े उन्होंने दे दिए और उत्तर प्रदेश का बजट बन कर आ गया। सही मायने में तो लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, चुनी हुई स्टेट की विधान सभाएं यदि बजट बनातीं तो उससे वास्तविक तौर पर जो गरीब गांव में रह रहा है, जो शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग गांवों में रह रहे हैं, उनको राहत मिलती। इस बजट से कहीं भी यह महसूस नहीं होता कि शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राहत देने के लिए कोई नई योजना प्रारंभ की गई है। इसलिए इस बजट के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रोज़गार देने के लिए, जो आज यू०पी० में शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों और महिलाओं के पास व्यवहार हो रहा है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए यदि इसमें प्रावधान होता, उनको राहत देने के लिए बजट में कुछ राशि रखी जाती तो अच्छा होता। यह तभी हो सकता था जब जन-प्रतिनिधि इस बजट को बनाते।

महोदय, कुछ दिन पहले मुझे एक शादी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिला। अभी बहन चन्द्रकला जी कह रही थी कि वहां की सड़कों की हालत

बहुत खराब है, हां यह बात सही है। सड़कें टूटी-फूटी हैं लेकिन एक बात और है। वहां की कानून और व्यवस्था ऐसी है कि आप रात में वहां चल ही नहीं सकते। सोमपाल जी कह रहे थे कि वे मेरठ से आते हैं। मेरठ में तो गैंग राज्य है। वहां दस-पंद्रह ऐसे गैंग हैं जिनका वहां राज्य है। मैं यह नहीं कहता कि पिछली सरकार जो जन-प्रतिनिधियों की बनी, उसने इसे कंट्रोल किया था लेकिन आज राष्ट्रपति शासन को लगातार तीन साल हो गए जिससे वहां की स्थिति और भयावह हो गई है। वहां का राज माफिया राज है। गरीब आदमी और जो कमज़ोर वर्ग है, उनका जीना हराम है वहां पर। उनका जीना जीना नहीं है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन को किसी तरीके से जितनी जल्दी हो सके, समाप्त किया जाए। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की बात करते हुए चाहे एक शेड्यूल्ड कास्ट की महिला को ही मुख्य मंत्री बनाएं लेकिन वहां पर कानून और प्रजातंत्र को लागू करें, लोकतंत्र की व्यवस्था करें, विधान सभा कायम करें जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून और व्यवस्था खराब हुई है, उसका एक मूल कारण शिक्षा रहा है। वहां की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उनका शिक्षा का जो स्तर है, वह बहुत गिर गया है। जितनी भी संस्थाएं हैं, वह फर्जी तरीके से चल रही हैं। गवर्नमेंट से जो ऐड मिलती है, उसे वह संस्था चलाने वाले अपनी जेब में रखते है। चाहे स्टूडेंट कॉलेज में जाए या नहीं, स्कूल में आए, नहीं पढ़े फिर भी उसको डिग्री दे दी जाती है। यू०पी० का तो एक धंधा रहा है। सारे हिन्दुस्तान के अंदर जितनी भी फर्जी डिग्रीज़ हैं, वह यहीं से प्राप्त होती हैं। हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी अगर फर्जी डिग्री लेना चाहता है, वह यू०पी० से लेकर जाता है इस प्रकार का धंधा हमारी शिक्षा संस्थाएं कर रही हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : अब समाप्त करिए, समय हो गया है।

श्री मूलचन्द मीणा: महोदय, इन पर प्रतिबंध तभी हो सकेगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर साम्प्रदायिक ताकतों और जातिवादी ताकतों को अपने आप वहां की जनता दूर कर देगी, हटा देगी, उनको समाप्त कर देगी। तब जाकर यू०पी० का विकास हो पाएगा। अभी सिब्ते रज़ी साहब कह रहे थे कि सात प्रधान मंत्री बने। आप सात प्रधान मंत्रियों की बात करते हैं, चाहे सौ प्रधान मंत्री बने लेकिन उत्तर प्रदेश की यही हालत रहेगी। जब तक यू०पी० के लोग मंडल और कमंडल की भावनाओं में बहते रहेंगे, तब तक यू०पी० का विकास नहीं हो सकता।

SHRI AKHILESH DAS (Uttar Pradesh): Sir, there is a point of order. It is very important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Under what rule?

श्री अखिलेश दास: जो हमारा उत्तर प्रदेश का बजट आया है, 1992 में कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था regarding municipalities and Panchayats. In that amendment, there is a mandatory provision that there will be a Finance Commission in the State. The Finance Commission was constituted in U.P. about three years ago. And it is a mandatory provision that that Finance Commission will give its recommendations.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): It is a question of fact. The Finance Minister will look into it and find out....

SHRI AKHILESH DAS: It is very important, Sir. That is why I want to raise it. The recommendations of the Finance Commission have not been included in this Budget, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Okay. That is all.

श्री मूलचन्द मीणा: महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस वित्तीय वर्ष के शेष बचे हुए भाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस बजट को राजनैतिक नहीं बनाना चाहता लेकिन श्री सिब्ते रज़ी साहब जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, उन्होंने बजट में सुझाव देने के बजाय, उसकी समीक्षा करने के बजाय, प्रदेश के विकास के लिए योजनाएं देने के बजाय पूरे का पूरा राजनैतिक भाषण दिया और फिर जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए, सबका राजनैतिक भाषण हो गया। मैं राजनैतिक भाषण नहीं देना चाहता हूं। केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव

हुए, वह धर्म-निरपेक्ष ताकतों और साम्प्रदायिक ताकतों के बीच हुए।

श्री नरेन्द मोहन: क्या यह राजनैतिक भाषण नहीं है?

श्री ईश दत्त यादव: नरेन्द्र मोहन जी, मैं विवश होकर आपकी बात का जवाब दे रहा हूं अन्यथा मैं नहीं बोलता। तो साम्प्रदायिक ताकतों और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच चुनाव हुए जिसमें धर्मनिरपेक्ष ताकतों को 232 सीटें मिलीं और एक छोटा सहयोगी दल लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 178 सीटें प्राप्त की। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मैं नरेन्द्र मोहन जी और राजनाथ सिंह जी की बातों का केवल इतना उत्तर देना चाहता हूं। हमारे सिब्ते रज़ी साहब के दिल में और उनकी पार्टी के दिल में दलित महिला के लिए बड़ा दर्द है। मान्यवर, 33 आदमियों की इनकी पार्टी है और जब नेता पद का चुनाव हुआ, 33 आदमियों में से नेता पद के चुनाव का समय आया तो उस समय किसी दलित का ध्यान इन्होंने नहीं किया, पिछड़ों का ख्याल नहीं किया। एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री इनकी पार्टी में हैं, उनको भी नेता बनाने का ख्याल इन्होंने नहीं किया तब दलित का ख्याल नहीं था। ये लोग केवल राजनैतिक लाभ के लिए दलित महिला कहते हैं। गुफरान जाहिदी साहब हमारे पुराने मित्र हैं, वह बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 809 ब्लॉक हैं। इन 809 ब्लॉक में लड़कियों के स्कूल नहीं हैं, कॉलेज नहीं हैं। मान्यवर, यह रिकार्ड की चीज़ मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे जो कि आज़ के रक्षा मंत्री हैं। हमारे संचार मंत्री माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री माननीय आज़म खान जी बैठे हैं इन्होंने एक फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश के हर ब्लाक में जहां लड़कियों का कालेज नहीं है वहां हम लड़कियों के लिए कालेज खोलेंगे। जो भी व्यक्ति या रजिस्टर्ड संस्था एक एकड़ भूमि उपलब्ध करा देगी तो हम वहां पर लड़कियों के लिए कालेज खुलवाने के लिए दस लाख रुपये देंगे। इस योजना पर विराम किसने लगाया?..... **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सिंह: यह तो भाजपा के शासन काल का है।

श्री ईश दत्त यादव: आप बैठिए, आप सुनने की आदत डालिए। उस योजना पर विराम किसने लगाया? जिस दलित महिला के लिए चिन्तित हैं हमारे सिब्ते रज़ी साहब और गुफरान जाहिदी साहब उसके ऊपर रोक लगा दी। आज हम इस सदन में रोना रो रहे हैं कि लड़कियों के लिए विद्यालय नहीं हैं। यह काम नहीं हो सका विकास का काम नहीं हो सका। विकास के काम को अवरुद्ध किसने किया? माननीय राजनाथ सिंह जी की पार्टी ने किया, जिनका 15 महीने तक शासन था! मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जैसे ही आपका आदेश होगा मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप अपना समय जानते हैं। आप उसी हिसाब से समाप्त कर दीजिएगा।

श्री ईश दत्त यादव: माननीय वित्त मंत्री जी की मैं प्रशंसा करुंगा कि जो सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों के अनुसार ही उन्होंने एक बजट देने का प्रयास किया है। यह मैं मानता हूं कि जितना इन्होंने प्रयास किया है उससे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था और इन्होंने कहा है कि जो बजट अनुमान था उसके बजाय संशोधित अनुमान में 669.73 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ी है और यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा समायोजन की मदों पर व्यय बढ़ने की बजह से करनी पड़ी है। इन्होंने जो व्यवस्था की है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं इस नाते से मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन मैं एक मुख्य विषय के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करुंगा, जिस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है और वह कृषि का विषय है। आज कृषि घाटे का व्यवसाय हो गई है। किसान जो भी अपने खेत में उत्पादन करता है उसका लाभकारी मूल्य किसान को नहीं मिल पा रहा है। आज किसान जो गन्न पैदा कर रहा है उसके गन्ने का जो पैसा होना चाहिए, उसका समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं हाई कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं हाई कोर्ट ने कहा है कि अब केन्द्र सरकार गन्ने का रेट तय करेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि देश के किसानों के हित में, प्रदेश के किसानों के हित में जल्दी से जल्दी गन्ने का अधिक से अधिक मूल्य निर्धारित करें। वरना देश के गन्ना उत्पादक किसान जो हैं वे हतोत्साहित हो जायेंगे, गन्ने की पैदावार कम होने लगेगी। यदि उनको उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो गन्ने की पैदावार कम हो जाएगी और चीनी का उत्पादन भी कम हो जायेगा और दो साल पहले जैसे सिब्ते रजी साहब की सरकार के समय में घोटाला हुआ था, देश के अन्दर चीनी का संकट पैदा हो जायेगा।

मान्यवर, देश के अन्दर जितनी सम्पत्ति पैदा होती है, दुनिया के अन्दर जितनी सम्पत्ति पैदा होती है और मैं कहने के लिए तैयार हूं कि वह सब पृथ्वी के अन्दर से आती है। चाहे अनाज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे रा-मैटीरियल हो, लोहा हो, कोयला हो, सब पृथ्वी के अन्दर से निकलता है और इनको निकालने वाला गांव में रहता है जिसका नाम किसान है, जिसका नाम मजदूर है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर नियन्त्रण रखना पड़ेगा। जो बजट अनुमान दिया है उसमें देखें कि इसका सदुपयोग किसान के हित में हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर किसान के हित में इसका उपयोग नहीं होगा तो देश की और प्रदेश की सारी व्यवस्था चरमरा जायेगी। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि राज्य पाल जी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का राज हो गया है और जैसा वे चाहते हैं वहां पर उनके स्थानान्तरण किए जाते हैं। जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं और खास करके समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहें हैं, आज भी वे अधिकारी अपने जिलों में बैठे हुये हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर शांति व्यवस्था कायम हो।

उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब का, शोषित का उत्पीड़न न होने पाये और भारत सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह इसको देखे। मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): समय आपका दुगुना समाप्त हो गया।

PROF. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot of deliberations have been made by various hon. Members about the Uttar Pradesh Budget. It is unfortunate that the U.P. Budget has been presented by the Central Government here, although, it should have been presented by the Uttar Pradesh Government because they could have better understood the aspirations and needs of the people. The economy of Uttar Pradesh, as everybody is aware, faces really a daunting task in the Eighth Five Year Plan and it should be set on the course of progress. The pace of economic development was exceptionally low and this has created shock weaves in the State Government. The Government itself admitted in its Mid-Term Apprisal Report that the U.P. economy faces a bleak future unless remedial steps are taken urgently. The Report squarely blames the Government itself for the poor state of economy. The average annual growth rate was just 2.4% as against the target of 6%. But the State not only failed to achieve the 6% target but fell below the national average of 4.8%. The main reasons given for the slow pace of growth are: economic development, political upheavals, uncertainity, inadequate mobilisation of resources and their utilisation, frequent changes in the Government, etc. These are all causes for the setback. The first two years of the Eighth Five Year Plan had witnessed the change of three Governments in Uttar Pradesh. Obviously, this may be the reason for not taking up long-term plans. There was a political uncertainity during the third year of the Plan. There are remote possibilities of political stability during the Fourth Plan. Besides, the report was highly critical of the inadequate mobilisation of resources by the Government and coupled with this was their low utilisation. The annual growth rate was also affected due to expenditure on productive schemes. The successive Governments had often gone in for populist schemes in utter disregard to the economic development. Sir, this was brought to light by the recent Report of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) and it was stated that the Non-Plan expenditure has increased from Rs. 4,727 crores in 1988-89 to Rs. 10,494 crores in 1992-93. Deficit financing is another problem which is affecting the pace of economic development. The report further says that the continued revenue deficit since 1988-89 had widened the gap between assets and liabilities. The State is also facing the problem of indebtedness which has not been taken care of by the Budget. Sir, it is found that while the annual *per capita*

income of the State is only Rs. 4,012, the per capita indebtedness is almost half of it and it stands at Rs. 2,181. Besides, Uttar Pradesh cannot hope to achieve economic progress because 24.3% of its population is living below the poverty line. Due to this, the *per capita* income is bound to be low and it affects and annual growth rate. However, the State Government considers the poor Central investment in U.P. as one of the reasons for the economic ills. Sir, you will be surprised to know that the Central Government contributed only 9.8% in U.P. though the State accounts for 16.5% of the population of the country. This has resulted in poor *per capita* investment. The mid-term apprisal recommends taking urgent measures to raise industrial and agricultural production. So far, in the Eighth Plan, the growth rate was below the target in both the sectors. The State Government should seek heavy investments in the infrastructure sector to encourage industrial production. In an agricultural State like U.P., there is scope for setting up more agro-industries. But, nothing has been done in this regard so far. With the increase in the State Government's borrowing leading to an enhancement in the debt burden and debt servicing, coupled with the limited resources at its disposal. The State's treasury may soon go bankrupt unless some hard decisions are taken to increase the tax revenue.

As regards U.P. Budget 1996-97 presented by the Central Government, it is strongly felt that there is need to provide more for social sectors like eduction, health, housing, etc. The position regarding utilisation of funds for these sectors requires continued monitoring which was not done at all in the past. In the annual report the Planning Commission has expressed anguish over non-utilisation by States of funds earmarked for social and infrastructure sectors. It is a sorry state of affairs. The financial discipline need not be compromised at any cost. The funds earmarked for social sector should not be diverted for revenue expenditure and should be fully utilised for that purpose only, so that the goals are achieved. Two important segments in the social sector, so far as U.P. is concerned, are female illiteracy and poor performance in family planning. Here the question that arises is, who is accountable for this? Another question is, why are funds not fully utilised in these sectors? The situation is to be corrected immediately.

The last factor is regional imbalance. Eastern U.P. requires a lot of development programmes. Why not concentrate on that part of U.P.? Similarly, the Uttarakhand region needs our serious attention. When such regions lay behind in the race for economic developments, they feel isolated and demand a separate identity. This happens when the fruits of planning are not properly distributed. Let the Government spend more on infrastructure and social sectors, opening more vistas of development, thereby bring more and more people into the mainstream of economic development.

Finally, financial planning and implementation and proper use of funds are necessary to achieve the desired goals. Otherwise, it is a case of bad supervision and bad management. Let this State emerge on the Indian map as a prosperous State. Under the circumstances mentioned above, I hesitate to support the Budget because it is not wholesome, since its emphasis should have been more on those sectors which have so far been ignored such as social sector and infrastructure sector which will produce goods and services and help in raising the living standards of the people and create opportunities for employment. Thank you.

SHRI AKHILESH DAS: Sir, I have a point of order....*(interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think it is not proper.

SHRI AKHILESH DAS: Sir, I will convince you. This Budget is incomplete. This Budget has been laid before...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mr. Das, you have made your point. The Finance Minister, when he replies, will reply to your question....*(interruptions)*...

SHRI AKHILESH DAS: Sir, I will complete by quoting....*(interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Whether that is complete or not, the Finance Minister alone can explain. I am making every effort that you get a few minutes...*(interruptions)* Please. Your Leader has already made a request on your behalf. I am doing my best. Please cooperate. Shri Jalaludin Ansari.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का 1996-97 का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का एक सबसे बड़ा राज्य है लेकिन यह प्रदेश पिछले कई वर्षों से राजनैतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। विधान सभा के चुनाव के बाद भी वहां राष्ट्रपति शासन के अंदर राज्य की जनता शासित हो रही है। अगर वहां कोई लोकप्रिय सरकार होती तो वह राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, दलित तथा पिछड़ों के विकास और बिजली की आवश्यकता के मुताबिक अपनी योजना बनाती और छोटे तथा मंझौले उद्योगधंधों के विकास के लिए अपनी आवश्यकता के अनुरूप वह बजट बनाती। लेकिन राष्ट्रपति शासन है इसलिए बजट तो इसी सदन में पास होना है। संसद् से पास होना है और जब केन्द्र से बजट बनाया जा रहा है तो जितनी वहां आवश्यकताएं हैं, उनको केन्द्र के अधिकारी और केन्द्रीय सरकार सही सही समझ नहीं सकते हैं। अभी हमारे माननीय साथियों ने जितनी तरह की बातें उठाई हैं, कुछ बाकी नहीं रहा है, प्रशासन और जनता के जितने काम हैं वह चलाए जा सकें। इसलिए इस बजट को लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। **(व्यवधान)** सभी जानते है जब घाटे का बजट होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी विद्वान हैं, अर्थ-शास्त्र भी कहता है कि घाटे का बजट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको एक लाइन पढ़ कर सुना देता हूं कि वर्ष 1996-97 के लिए राज्य की आयोजना में 5440.64 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये का अनंतिम परिव्यय शामिल है। उपरोक्त राशि में 833.39 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है, जिसे बाहर के संसाधनों से जुटाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह बाहर से जुटाने का स्रोत क्या है? यह आप नहीं बताते हैं। जुटाया जाएगा, इसी आशा पर है। 1996-97 के बजट में मात्र दो हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई 1995-96 के मुकाबले में। यहां बहुत तरह के राजनीतिक आक्षेप और आरोप लगाए गए हैं। कौन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो मैं उस चर्चा मे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह भी लोगों ने कहा कि सत्य नहीं बोलते हैं। जब सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाएगा। यू०पी० के अंदर जो स्थिति है उसका भी हल सत्य को कबूल करेंगे तभी निकलेगा और इसके लिए जिम्मेदारी सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के भाइयों की है जिन्होंने यहां तक पहुंचा दिया। मंडल भी आ गया और कमंडल भी आ गया। अगर ये ठीक होते तो न मंडल आता, न कमंडल आता और न यह स्थिति होती। बाद में हमारे भा०ज०पा० के भाइयों ने भी उस दुर्दशा तक पहुंचा दिया जिसके लिए आज रोना रो रहे हैं।

सैयद सिब्ते रज़ी: आप तो हर हाल में मजा लेते हैं.

(व्यवधान)

श्री जलालुदीन अंसारी: हमारे को अपने हाल पर छोड़ दीजिए **(व्यवधान)** आप कहां चले गए हैं। आप अपने हाल को देखिए। हमारे हाल पर मत जाइए.

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है उपसभाध्यक्ष महोदय कि राजनीतिक पार्टी हम और आप सब हैं। अपने विचार और सिद्धांत भी रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा आप लोग कब तक करते रहेंगे। उसके हितों के बारे में, उनके विकास के बारे में अगर आप कोई सही रास्ता नहीं निकालते है तो जनता ने अभी जहां पहुंचा दिया है हो सकता है आगे कोई और दूसरा रास्ता निकाले। इसलिए जरूरी है कि वहां एक लोकप्रिय सरकार बनाएं मैंने पिछली बार भी बोलते हुए कहा था कि जिद पर मत रहिए। जनता की इच्छा और उसकी जरूरियात का ध्यान रखते हुए वहां सरकार बनाइए चाहे सरकार किन्हीं भी दलों के गठबंधन की हो लेकिन एक लोकप्रिय सरकार ही वहां के विकास के लिए रास्ता निकाल सकती है और यह बार बार का राष्ट्रपति शासन और उस राष्ट्रपति शासन के अंदर बजट पास करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हम न्याय नहीं कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बजट का समर्थन करते हैं।

†المفتی جلال الدین انصاری "بہار": اپ سبھا ادھیکش مہودے - اتر پردیش کا ۱۹۹۶-۹۷ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے - اتر پردیش دیش کا ایک سب سے بڑا راجیہ ہے - لیکن یہ پردیش پچھلی کئی ورشوں سے راجنیتک استھرتا کے دور سے گزر رہا ہے ودھان سبھا کے چناؤ کے بعد بھی وہاں راشٹرپتی شاسن کے اندر راجیہ کی جنتا ترست ہو رہی ہے - اگر وہاں کوئی روک پرپہ سرکار ہوتی تو وہ راجیہ کی آوشیکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرشی - ادھیوگ - شکشا - سماج - کلیان - دلت تتھا پچھڑوں کے وکاس اور بجلی کی آوشیکتا کے مطابق اپنی یوجنا بناتی اور چھوٹے تتھا منجھولے ادھیوگ دھندوں کے وکاس کیلئے اپنی آوشیکتا کے انوروپ وہ بجٹ بناتی - لیکن راشٹرپتی شاسن ہے اسلئے بجٹ تو اسی مہینہ سے پاس ہونا ہے - سنسد سے پاس ہونا ہے اور جب کیندر سے بجٹ بنایا جا رہا ہے تو جتنی وہاں آوشیکتائیں ہیں - انکو کیندر کے ادھیکاری اور کیندر کے سرکار سہی سہی سمجھ نہیں سکتے ہیں - ابھی ہمارے ساتھیوں نے جتنی طرح کی باتیں اٹھائی ہیں - کچھ باقی نہیں رہا ہے اسلئے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں - لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کا سب سے بڑا راجیہ جو پچھڑا ہوا ہے اس راجیہ کا بجٹ پیش ہو تو راجیہ کے پچھڑے پن کو دور کرنے کیلئے بجٹ میں اگر وشیش دھنراشی کی ویوستھا اتھوا اسکی یوجنا نہیں ہو گی تو نشچت طور پر مانا جائیگا کہ راجیہ کے وکاس کیلئے بجٹ نہیں ہے بلکہ اس راجیہ کے شاسن اور پرشاسن کو چلانے کی آوشیکتا کیلئے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس بجٹ کو پاس کرنا ہے - میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا پردیش ہے - شکشا کی چرچا سبھی لوگوں نے کی ہے - بندر کی چرچا کی ہے - صرف یہاں کی شکشا کے معاملے میں جو استھتی ہے وہ پورے دیش کے لوگ جانتے ہیں لیکن اس پردیش کے بچے اپنے ادھیوگ دھندے ہیں - چوڑی ادھیوگ - برتن ادھیوگ - تالا ادھیوگ - قالین ادھیوگ - کپڑا ادھیوگ - آج ان ادھیوگوں کی استھتی کیا ہے - اور اس بجٹ میں ان ادھیوگوں کو بڑھانے کیلئے الگ سے کوئی ویوستھا نہیں ہے اس

†Transliteration in Arabic Script

داشی شامل نہیں ہے - جیسے باہر کے سنسادھن سے جٹایا جائیگا - میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باہر سے جٹانے کا سروت کیا ہے - یہ آپ نہیں بتائے ہیں - جٹایا جائیگا - اسی آشا پر ہیں - ۹۷-۱۹۹۶ کے بجٹ میں ماتردو ہزار کروڑ کی بڑھوتری کی گئی ۹۶-۱۹۹۵ کے مقابلے میں یہاں بہت طرح کے راجسٹک اکشیپ اور آروپ لگائے گئے ہیں - کون اس استھتی کے لئے ذمہ دار ہے - تو میں اس چرچا میں نہیں جانا چاہتا ہوں - لیکن یہ بھی لوگوں نے کہا کہ سنتھائے نہیں پورتے ہیں - جب سنتھائے پورا شروع کر دیں گے - تو بہت ساری سمسیاؤں کا حل اپنے آپ نکل جائیگا - یو - پی کے اندر جو استھتی ہے اسکا بھی حل سنتھائے تو قبول کر لیں گے

تبھی نکلے گا - اور اسکے لئے ذمہ داری سب سے پہلے تو ہمارے کانگریس کے بھائیوں کی ہے جنہوں نے یہاں تک پہنچا دیا - منڈل بھی آگیا اور کمنڈل بھی آگیا - اگر یہ ٹھیک ہوتے تو نہ منڈل آتا نہ کمنڈل آتا - اور نہ یہ استھتی ہوتی - بعد میں ہمارے بھاجپائی بھائیوں نے بھی اس درد شا تک پہنچا دیا جسکے لئے آج رو رہے ہیں -

چھیتر میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں انکی جو دینے استھتی ہے - اسکو دور کرنے کیلئے بھی اس بجٹ میں اپیورتیں کی جا سکتی ہے - اسلئے میری سمجھ یہ ہے کہ ابھی ابھی شاسن اور پرشاسن چلا رہا ہے - اسکے یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے تا کہ وہاں راشٹرپتی شاسن میں شاسن - پرشاسن اور جٹانے جتنے کام ہیں وہ چلائے جا سکیں - اسلئے اس بجٹ کو لایا گیا ہے - میں اسکا سمرتھن کرتا ہوں - اسکے علاوہ کوئی دوسرا جاوہ بھی نہیں ہے - "بمد داخلت" سبھی جانتے ہیں جب گھاٹے کا بجٹ ہوگا تو مہنگائی بھی بڑھے گی - ہمارے مالیہ وت منتری جی خود وہاں ہیں - ادھیکشا جی بھی کہتا ہے کہ گھاٹے کا بجٹ ہوگا تو مہنگائی بڑھیگی - مدد استھتی بڑھیگی اسکو آپ روک نہیں سکتے ہیں - میں آپکو ایک لائن پڑھکر سنا دیتا ہوں کہ ورش ۹۷-۱۹۹۶ کیلئے راجیہ کی آیوجنا میں ۵۲۰۰۰۶ کروڑ روپئے کی ویوستھا کی گئی ہے جسمیں پہاڑی چھیتروں کے وکاس کا ویکرموں کے انترگت ۲۲۵ کروڑ روپئے کا انتم پریوے شامل نہیں ہے - اپرولکت راشی میں ۸۳۳۰۳۹ کروڑ روپئے کی

†Transliteration in Arabic Script

سید سبط رضی: آپ تو ہر حال میں مزہ لیتے ہیں۔۔۔"مداخلت"۔۔۔

شری جلال الدین انصاری: ہمارے کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔۔۔"مداخلت"۔۔۔ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ آپ اپنے حال کو دیکھئے ہمارے حال پر مت جائیے۔۔۔"مداخلت"۔۔۔ میرا نوٹ ہے آپ سبھا ادھیکشن مہودے۔ کہ راجنیتک پارٹی ہم اور آپ سب ہیں۔ اپنے وچار اور سدھانت بھی رہیں گے۔ لیکن اتر پردیش کی جنتا کی آکانشاؤں کی اپیکشا آپ لوگ لب تک کرتے رہیگے اسکے حقوق کے بارے میں۔ اسکے وکاس کے بارے میں۔ اگر آپ کوئی سہی راستہ نہیں نکالتے ہیں تو جنتا نے ابھی جہاں پہنچایا ہے ہو سکتا ہے آگے کوئی اور دوسرا راستہ نکالے اسلئے ضروری ہے کہ وہاں ایک لوک پریہ سرکار بنائیں۔ میں نے پچھلی بار بھی بولتے ہوئے کہا تھا کہ ضد پر مت جائیے۔ جنتا کی اچھا اور ضروریات کا دھیان رکھتے ہوئے وہاں سرکار بنانے چاہیے سرکار کہیں بھی گٹھ بندھن کے دلوں کی ہو۔ لیکن ایک لوک پریہ سرکار ہی وہاں کے وکاس کیلئے راستہ نکال سکتی ہے اور یہ بار بار کا راشٹرپتی شاسن کے اندر بجٹ پاس کرکے اتر پردیش کی جنتا کے ساتھ ہم نیائے نہیں کر سکتے ہیں۔ انھیں شبدوں کے ساتھ ہم اس بجٹ کا سمرتھن کرتے ہیں۔ "ختم شد"]

†Transliteration in Arabic Script

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): धन्यवाद। देवी प्रसाद सिंह। पांच मिनट में आप अपना वक्तव्य समाप्त कर दीजिए ..(**व्यवधान**) जी नहीं। वसीम अहमद साहब है नहीं। इसके बाद बस आजम खान साहब और श्री दास एक मिनट के लिए। वैसे उन्होंने अपनी बात कह दी है।

श्री देवी प्रसाद सिंह (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन सारे साथियों के प्रति सहानुभूति रखता हूं जो दिल से तो विरोध करते हैं बजट का लेकिन मजबूरी में उनको समर्थन करना पड़ रहा है। कौन सी मजबूरी है यह वे जानते हैं, और वह मजबूरी है भा०ज०पा० कहीं विरोध करें तो सरकार न गिर जाए और सरकार गिरेगी तो भा०ज०पा० आएगी। यह इनकी मजबूरी है ..(**व्यवधान**) यह तो देखा जाएगा। लेकिन आज आप जिस कफस में है जिस कफस में बोल रहे हैं कि मजबूरी में हमें पास करना पड़ रहा है यह बजट, मान्यवर उस पर मुझे सिर्फ तरस आ रहा है। मैं बजट पर सीधे आ रहा हूं। थोड़ी शुरू में चर्चा हो गयी थी इसलिए कह रहा हूं अभी थोड़ी सी चर्चा हुई कि राज्य सभा ने भा०ज०पा० को अपनी ताकत दिखला दी। भा०ज०पा० हार गयी। मान्यवर, शायद हमारे दोस्तों को गिनती की जानकारी नहीं। भा०ज०पा० तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 173 सीटें जीती थी। दो समता पार्टी को लेकर चलें तो 175 हो गयीं और चुनाव हुए तो भा०ज०पा० को दो सौ मत मिले। भा०ज०पा० हारी नहीं। भा०ज०पा० जीती है चुनाव।

एक माननीय सदस्य: पैसे से।

श्री देवी प्रसाद सिंह: इसलिए हमारे दोस्तों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए और जो जो संख्या आयी इसमें 18 की संख्या बढ़ी। उसमें आप लोगों ने ही वोट दिए। अगर आप लोगों में से 18 दे सकते हैं तो हमारी सरकार बनेगी। हमारी संख्या 211 से ऊपर जाएगी। लेकिन आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसलिए वहां सरकार नहीं बनने दे रहे हैं। एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको मदद करना चाहिए, आपको मदद

करनी चाहिए, आपको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इकट्ठा कोई भी होता नहीं। कहते तो है कि 232 की संख्या आपकी है। अपने को धर्म निरपेक्ष बताते हैं लेकिन दो महीने हो गए मान्यवर और उत्तर प्रदेश में सरकार अभी तक नहीं बन पायी है। हमने बनाने का दावा किया लेकिन हमको बनाने नहीं दे रहे है और आप बना नहीं सकते। आज स्थिति यह हो गयी है कि उत्तर प्रदेश का बजट हमें राज्य सभा में पेश करना पड़ रहा है। ये सारे वे लोग हैं जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दशा पर कोई सड़कों की बात कर रहा है, कोई किसानों की बात कर रहा है। वे सारी बातें कर रहे हैं जो हमें यहां नहीं करनी चाहिए, फिर भी ये बजट का समर्थन कर रहे हैं।

"अजीब माजरा है कि बरोज़ ईद कुरबान,
खुद ज़िब्ह भी करे है और ले सवाब उलटे।"

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी मेरे पास मेरी पार्टी का बहुत समय बचा हुआ है। इस बजट में देखा गया कि सारा कुछ है, किसानों के बारे में कुछ नहीं है। गन्ना किसान 1/3 है इस प्रदेश में और गन्ने का पैसा बकाया है। पेराई की समस्या है। बकाया पैसे के भुगतान का कोई उपाय नहीं है। गन्ने की पेराई कैसे होगी इसका कुछ पता नहीं है। वह गन्ना किसान गन्ने का क्या करेगा उसका बजट में कोई प्रोविज़न नहीं है। रबी की बुवाई का समय है। बीज का कुछ पता नहीं। खाद मिल नहीं रही है। किसान अगर मरेगा तो प्रदेश मरेगा। इसलिए किसान के बारे में हमारी इस सरकार ने कोई चिंता नहीं की है जिन्होंने बजट की बात की है। जिन्होंने बजट बनाया वे कौन लोग हैं! बजट चुनी हुई सरकार ने नहीं बनाया है, किसी पापुलर सरकार ने नहीं बनाया है, बल्कि यह बजट तो उन अधिकारियों ने बनाया है जिन्होंने लोकशाही पर, नौकरशाही पर कब्जा बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो हमने सोचा था कि चुनाव होंगे, सरकार बनेगी। एक पापुलर गवर्नमेंट आएगी। लेकिन यह चुने हुए जनता के लोग आज सड़कों पर घूम रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में नौकरशाह शासन कर रहे हैं। जनता द्वारा चुने हुए लोग अपने क्षेत्र में जा नही पा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। यह सरकार रहेगी या खत्म होगी, यह चिंता बनी हुई है। बस खत्म कर रहा हूं

मान्यवर, आखिरी बात है। मैं चाहता था कि शूगरकेन ग्रोवर्ज़ की समस्याओं के बारे में सोचा जाता। उत्तर प्रदेश में एक थोड़ी सी बात और होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। उसमें से एक कुशीनगर आता है। अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कुशीनगर को पूरे बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाए। यानी बुद्धिस्ट सर्किट का सैकंड फेज़ पुनः चालू किया जाए। उसे सड़क मार्गों से जोड़ा जाए, रेल मार्ग से जोड़ा जाए और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाए। उससे दो फायदे होते एक तो वह बुद्धिस्ट सर्किट पूरी हो जाती और दूसरे हमारे देश को फारेन करेंसी का लाभ होता है। यदि इस पर विचार किया जाता तो शायद इस हिसाब से हम कुछ कर पाते। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पिछड़ा इलाका है। रोज़गार का कोई वहां साधन नहीं है, कोई फैक्टरी नहीं, कोई मिल नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कोई ऐसा प्रावधान रखिए कि उस इलाके में भी कुछ उद्योग लगें और उद्योग-धंधे बढ़ें। वहां का पिछड़ापन समाप्त हो।

अंतिम बात अपने दोस्तों से कह कर खत्म करूंगा कि भा०ज०पा० पर छींटाकशी न करें। अपने दामन पर देखें। हम भा०ज०पा० को तो भा०ज०पा० रहना है। कि, लें। यह सब की अपनी मर्जी है, लेकिन यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले लगभग 12 करोड़ लोगों ने इस बात को यकीनन नकार दिया है कि उस प्रदेश में कोई ऐसी सरकार न आने पाए जो कि इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करे, जो एक दूसरे को लड़वाने का काम करें क्योंकि ऐसी सरकारें भी उस प्रदेश में आई हैं जिन्होंने विकास का काम किया है। दो बार हमें सरकार बनाने का, मुलायम सिंह जी को सरकार बनाने का मौका मिला है और उस वक्त हम ने जनता के सामने पूरी ईमानदारी के साथ यह साबित किया है कि अगर धर्म की राजनीति न की जाए, किसान को पानी दिया जाए, उस को सस्ता बीज दिया जाए, उसे खाद दी जाए, उसे बिजली मिले, कारखानों में काम करनेवाले को

"इस सदन में मैं अकेला ही दीया हूं,
मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे
मिलेगी।"

धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Shri Wasim Ahmad not present.

Shri Azam Khan.

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बहत से साथियों ने बड़ी मजबूरी के आलम में

इस बजट को पास करने की या इसकी हिमायत में अपनी बातें कही हैं। शायद ऐसा ही एक मजबूर मैं भी आपके सामने खड़ा हूं।

"ज़ब्त-ए-ग़म इश्क में रोने नहीं देता मुझको,
आज आंसू भी मेरे कैद से आज़ाद नहीं।"

तो वाकई यह आलम पूरे सदन का है और यह सच बात है, बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश देश का सब से बड़ा प्रदेश होने के बावजूद, सब से बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद और यहां जैसा सिब्ते रज़ी साहब ने कहा कि है ऐसा अभागा प्रदेश जिसने बहुत से प्रधान मंत्री दिए।

6.00 P.M.

लेकिन वह प्रधान मंत्री अपने ही प्रदेश को कोई तकदीर नहीं दे सके, कोई दिशा नहीं दे सके। एक ऐसा प्रदेश जिस के पास आज अपनी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है और यह सही है कि होना तो यह चाहिए कि सदन के अंदर, सदन में बैठने वाले लोग बजट पास करें। यह भी सही है कि कोई चुनी हुई सरकार उस प्रदेश का भविष्य तय करे, लेकिन हमारे कुछ साथी जो यहां सरकार बनाने की बात कर रहे हैं या सदन में बजट पास करने की बात करते हैं, उन्हें शायद कानून की वह कमजोरियां मालूम नहीं है जिसके बिना पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री, राज्यपाल, तानाशाह और बादशाह-सब कुछ होने का सौभाग्य प्राप्त है। एक ऐसा राज्यपाल जिस ने सिर्फ़ गोल्फ ही नहीं खेला है और भी बहुत कुछ खेला है। वाजिद अली शाह जो लखनऊ की सरजमीं या अवध की सरजमीं पर बहुत चर्चित और जाने गए, उन की तारीखों को तोड़ने का भी काम किया है। यह बड़ी विडम्बना है। यह सही है, लेकिन सदन सरकार जब तक नहीं बनाएगा, विधायक जब तक सरकार नहीं बनाएंगे या शपथ जिस की बात आप ने कही है, उस वक्त तक किसी चुनाव की बात भी नहीं चलेगी और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल या किसी प्रदेश का राज्यपाल किसी सरकार का गठन नहीं कर सकता बल्कि हमारे भाजपाई साथियों की, 13 दिन की सरकार बनाने की ख्वाहिश अगर पूरी भी कर दी जाए, उस के बाद भी कोई नया नक्शा नहीं बनता। इसलिए शायद अब इस की दावत उन्हें मिलने वाली नहीं है हालांकि मांग बहुत है।

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जैसाकि ईश दत्त यादव जी ने कहा और यह सही है कि इस बजट पर राजनीतिक भाषण नहीं होने चाहिए थे बल्कि बजट की अच्छाइयों और बुराइयों की बात होनी चाहिए थीं। उस में विकास के कामों की कितनी गुंजाइश है, इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन जितनी बातें हुई, वह सिर्फ मजबूरी के आलम में हुई। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, मान्यता सब की यही है कि चुनी हुई सरकार हो, चुने हुए लोग सदन के अंदर फैसला उस की मेहनत की उजरत मिले, गरीबों की पेंशन में इज़ाफा हो—60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक इज़ाफा हो, पहली बार एक ऐसा प्रदेश जिसमें किसानों को पेंशन दी जाए वह लोग जिन्हें चोर समझकर पुलिस पकड़कर ले जाए, जो किसी की मिट्टी चुराकर बर्तन बनाए, उन को चोर नहीं बल्कि स्वामी बना दिया जाए, समाज का वह वर्ग जिसे पहले समाज में जीने का कोई हक हासिल न था, ऐसी सरकारें भी उत्तर प्रदेश में आईं जिन्होंने उन्हें जीने का हक दिया। ऐसी जुबानें जो इस मुल्क में मुजरिम जुबानें मानी गयी थीं, उन को सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि पनपने का मौका दिया और सिर्फ यह नहीं कहा गया कि इसे दूसरी राजभाषा बना दिया जाएगा। एक ऐसे मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाने के लिए दो बार बिल पेश किया, लेकिन दोनों बार वह बिल अपनी मौत खुद मर गया, कानून नहीं बन सका। हम ने दूसरी भाषा बनाने का झूठा वायदा नहीं किया बल्कि हम ने यह कहा कि हम उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ेंगे और तकरीबन साढ़े 6 हजार खानदानों को जो कभी यह सोच नहीं सकते थे कि उन्हें सरकारी मुलाजमत मिलेगी, उन्हें सरकारी मुलाजमत से जोड़ने का काम किया। लेकिन आज के बजट में एक बड़ी विडम्बना यह है, अंसारी जी ने भी जिस की तरफ इशारा किया है कि कोई बजट उस वक्त तक कामयाब बजट नहीं हो सकता जब तक वह उस प्रदेश की उस जनता से न जुड़ जाए जिन के पास पहनने के लिए कपड़ा न हो, जिन के पास खाने के लिए रोटी न हो और सिर छुपाने के लिए आसरा न हो। हमारे करोड़ों मजदूर भाई ऐसे हैं—चाहे वह बुनकर भाई हों, कारखानों में काम करने वाले लोग हों, खेतिहर मजदूर हों या हमारे झिल्ली ढोने वाले मजदूर हों, जब तक उस के कल के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, उस वक्त तक वह बजट कामयाब नहीं हो सकता।

आज हमारे सदन में कुछ कारखाने बेचने की बात आई है, जैहदी साहब ने भी प्राइवेटायजेशन के बारे में कहा, लेकिन बदलते हुए हालात में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मजबूरियों के सौदे हैं। हमारे सरकार ने फैसला लिया था। वह कारखाने जो कि उस प्रदेश पर सफेद

हाथी बने हुए हैं और खुद कानपुर इस की मिसाल है। कानपुर किसी जमाने में हिंदुस्तान का मैनचेस्टर था, वहां आज शहर के अंदर सैकड़ों बीघा नहीं बल्कि हजारों-लाखों गज ऐसी जमीन है जो कि सोने और हीरे के दामों में बिकनेवाली है, लेकिन वह पूंजीपतियों के कब्जे में हैं और वे उस को नहीं छोड़ना चाहते।

पूंजीपति का ख्वाब यह है कि कभी न कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो इन कारखानों को बेचकर, उसकी जमीनों के पैसे पर उन्हें अय्याशी करने का मौका देगी। हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ यकीनन् फैसला लिया था लेकिन उसकी मंशा यह हरगिज़ नहीं थी कि अगर हम बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो हम किसी पूंजीपति को कुछ कमाने देने का मौका देना चाहते हैं या कपड़े के कारखानों को या दूसरे कारखानों को हम अगर बेचने की इजाज़त देना चाहते हैं तो वह इसलिए नहीं कि हम किसी एक का भला चाहते थे या किसी के नाम के साथ जोड़कर हम उसे बेचना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उत्तर प्रदेश को बिजली चाहिए और प्राइवेट लोग, प्राइवेट कारखाने बिजली बनाएं लेकिन सरकार उसके डिस्ट्रिब्यूशन का काम करे। इसी तरह वह जमीन, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीन है, 12 करोड़ जनता की जमीन है या 95 करोड़ हिन्दुस्तानियों की जमीन है, उस जमीन को बेचकर वह सारा धन पूंजीपति का नहीं होगा बल्कि सरकार के खजाने में दाखिल होगा। इस तरह की व्यवस्था भी इस बजट में होनी चाहिए थी, जो नहीं है, इसका यकीनन् खेद है। सच्चाई यह है कि जिस तरह तमाम साथियों ने बड़ी मजबूरी के आलम में इस बजट को पास करने की सिफारिश की है, उसी मजबूरी के आलम में उन गवर्नर साहब की खिदमत में यह कहना चाहता हूं कि 25 तारीख से गोवा तशरीफ ले जा रहे हैं पूरी मंडली के साथ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि 25 तारीख के बाद भी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे सवाल खड़े होंगे जिनमें कानून और व्यवस्था का भी सवाल होगा, गरीबों के उत्थान और उद्धार का भी सवाल होगा। तो हमारे गवर्नर साहब को उत्तर प्रदेश को किसी अच्छी तरफ ले जाने की कोई किरण नज़र आती हो तो बजाए इसके कि 25 तारीख से 1 तारीख तक का छोटा-बड़ा दिन जाकर गोवा में देखें, उत्तर प्रदेश के गरीबों में ही रहकर छोटे बड़े दिन को देखने का अगर काम करें तो अच्छा हो। तो, बहरहाल, यह एक ख्वाहिश हो सकती है, एक शहरी के नाते इस ख्वाहिश का हक है मुझे और मैं इस ख्वाहिश को करना चाहता हूं और आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

उसी मजबूरी के आलम में, जो सबकी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी है कि प्रदेश को चलाने के लिए, वहां के कर्मचारियों की तनख्वाहें देने के लिए, वहां के लोगों के लूले-लंगड़े विकास के लिए इस बजट की मैं भी हिमायत करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

revised paragraphs ot the Actoin Taken Report on the report of the JPC which was placed before Parliament in December, 1994. I believe, this contains the action taken on the JPC's recommendations.

Mr. Narayanasamy also raised the question of NPAs. It is a very important question. The NPAs. of the banking system, today—as a number of hon. Members have mentioned—amount, approximately, to Rs. 40,000 crores. But the silver-lining in the cloud is, while the NPA ratio has...

SHRI SATISH AGARWAL: Gone down.

SHRI P. CHIDAMBARAM: While the NPA ratio has declined substantially—it is now, approximately....

SHRI SATISH AGARWAL: Nineteen per cent.

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is 19 per cent or so.

While the NPA ratio is 19 per cent or so, lending after 1992-93 the NPA is only 3.5 per cent. This is the silver-lining. The bulk of the NPAs. are prior 1992-93 NPAs. While the percentage of NPAs. to the total advances appears to be large, in the post 1992-93 period, after the norms were established, the NPA percentage, i.e. incremental NPA to incremental lending, is only 3.5 per cent.

3.00 P.M.

It means, banks are now more careful in lending, banks are more vigilant, there is better quality of lending and there is better recovery of loans. As to what we have to do about the old loans, I am addressing the questions. The Chairmen have suggested to me a method, I have suggested to them a method. Only five or six banks require a special mechanism.

For example, some banks are doing pretty well in recovery. Some banks are unable to do so, partly because of fear, partly because of the complexity of the cases. We are trying to find a system by which the pre-1992 NPAs, what I call, the sticky NPAs, can be quickly resolved by a speedy way of settlement. There is no point in carrying these NPAs in your balance sheet. Any businessman will know that an old loan is no satisfaction Although it is shown as an asset, it is no satisfaction: it remains in the book. It is much better that you recover something. But we will have to find a way in which the old NPAs can be liquidated in a transparent and open manner and the quality of lending, which has improved after 1992, is maintained so that the NPA percentage drops sharply in the years to come.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): दास साहब, आपका क्या प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री अखिलेश दास: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): बस प्वाइंट आफ आर्डर बता दीजिए।

श्री अखिलेश दास: मुझे यह कहना है कि आर्टिकल 243 आई कांस्टीट्यूशन का जो है, उसमें यह प्रोविज़न है कि: "The Governor of a State shall, as soon as may be within one year from the commencement of the Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992 and thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and to make recommendations to the Governor as to—

प्वाइंट आफ आर्डर इसमें यह है कि इस बजट के अंदर, उत्तर प्रदेश में फाइनेंस कमीशन तीन साल पहले गठित हो चुका है और उसके तहत, उसकी रिकमेंडेशन इसके अंदर इन्कलूड होनी चाहिए थी। "(a) the principles which should govern—(i) the distribution between the State and the Panchayats of the net proceeds of the taxes, duties tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under this Part and the allocation between the Panchayats at all levels of their respective shares of such proceeds;

और, सर, आर्टिकल 243 आई (4) में है कि:—

"(4) The Governor shall cause every recommendation made by the Commission under this article together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the Legislature of the State;"

तो, सर, इस बजट के अंदर यह चीज़ नहीं लागू की गई है। दिस इज़ ए कांस्टीट्यूशनल मेंडेटरी प्रोविज़न। सिर्फ यह कह देना कि रिकमेंडेशन आई या नहीं आई पर्याप्त नहीं है, रिकमेंडेशन आना मस्ट है। गवर्नर को इस बात को इम्फेसिस करना चाहिए था बजट देने से पहले।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): फाइनेंस मिनिस्टर साहब कल उत्तर देंगे और उस समय क्या स्थिति है, जो आपने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है उस बारे में, वह बताएंगे और मैं समझता हूं कि अगर इसमें वास्तव में कानूनी या संवैधानिक तौर से कोई कमी है तो उसको वह पूरा करेंगे।

श्री अखिलेश दास: थैंक्यू वाइस चेयरमैन सर।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points Arising out of answer to Starred Question No. 83 Regarding Implementation of National Telecom Policy

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Now, we will take up half-an-hour discussion. Shri Ajit Jogi. Not here. Shri Satish Agarwal.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to raise this half-an-hour discussion regarding implementation of the National Telecom Policy. The necessity of this discussion arose out of the answers given to the Starred Question No. 83 by the hon. Minister on the 27th November, 1996. Mr. Vice-Chairman, you may kindly recall that two years back the National Telecom Policy was announced in this House with great fanfare Probably on the 13th May, 1994 that